certainly do that. But it does not arise here. I have not got the figures.

12.37 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATIONS UNDER ESSENTIAL COMMODITIES ACT, 1955

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): I lay on the Table a copy each of the following Notifications under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act 1955:—

(1) The Rajasthan Foodgrains (Restrictions on Border Movement) Fourth Amendment Order, 1967, published in Notification No GSR 989 in Gazette of India dated the 29th June, 1967.

(2) GSR 1031 published in Gazette of India dated the 3rd July, 1967, making certain amendments to Notification No. GSR 1842 dated the 24th December, 1964 [*Placed in Library, See* No LT-975/67].

12.17½ hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

FOURTH REPORT

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh): I beg to move

"That this House agrees with the Fourth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 10th July, 1967."

Shri Bal Raj Madhok (South Delhi) Sir, in this connection, we have suggested that besides sitting on two Saturdays, we might do away with the Lunch Hour, or, we might sit an hour late, say, up to 7 P.M., so that the Demands for Grants could be discussed, as many Demands as possible. (*Interruption*)

Mr. Speaker: I do not know The motion is now there. The Business Advisory Committee discussed all this But even at 5 o'clock, if you do not keep the quorum, I wonder if you will be able to keep the quorum after 6 P.M. I find that sometimes, except some Members who want to speak, the rest go away I do not know. If you keep the quorum, you can continue up to 7 also. Nobody objects.

श्री राम सेवक यादव :(बाराबंकी) मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि डा० राम मनोहर लोहिया का खर्च पर रोक के सम्बन्ध मे जो प्रस्ताव है वह कब लिया जा रहा है—इस हफ्ते या अगले हफ्ते।

Mr Speaker: That has nothing to do with this report. This is only about sitting on Saturdays and the Demands for Grants That is a separate item Next week, we shall meet again, and fix up the programme for the next week But this is only about the Demands for Grants and the extension of time for the Demands so that Demands of two more Ministries can be discussed and a third one, if possible. But the minimum is two—Education and Petroleum and Chemicals, and if possible, Steel also could be taken up. About Mr. Madhok's suggestion, if they are prepared to sit till 7 P.M., nobody objects. We shall see, Now, the question is:

"That this House agrees with the Fourth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 10th July, 1967."

The motion was adopted.

*DEMANDS FOR GRANTS 1967-68—contd.

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS—contd.

Mr. Speaker: The House will now taken up the Demands for Grants under the Department of Communications We have got a balance of 1 hour 50 minutes. Dr Ram Subhag Singh will reply roundabout 3.30 P.M. So, I think up to 3 30 we may discuss the Demands and that will be all right, I suppose Now, who was speaking yesterday?

*Moved with the recommendation of the President

An hon. Member: The Minister of State intervened and he finished.

Mr. Speaker: Mr. Rabi Rai may speak. He has got 8 minutes.

श्री रवी राय : हमारी तरफ से आर्य फरनेन्डीज का नाम गया है।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): We have given Mr. Sarjoo Pandey's name.

Shri S. Kundu (Balasore): Mr. Ram Charan will speak on behalf of PSP.

श्री सरजू पाण्डेय (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय हम लोग जिस डिमांड के ऊपर बहस कर रहे हैं वह हमारे देश के बहुत महत्वपूर्ण विभाग से सम्बन्धित है। इस विभाग के अन्दर पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ, वायरलेस, प्लानिंग एंड कोआर्डिनेशन, ओवरसीज कम्युनिकेशन्स, इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, लिमिटेड, बंगलौर, हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड, मद्रास यह पांच विभाग आते हैं। सब से पहला हमारा आरोप यह है कि यह विभाग जो जनता की सेवा इसे करनी चाहिए वह नहीं कर पा रहा है और इतना महत्वपूर्ण विभाग रहते हुए भी हमारे देश की करोड़ों जनता को इस विभाग के द्वारा परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। माननीय मंत्री जी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें इस विभाग का बड़ा गुणगान किया गया है और इसकी बहुत सारी बातों में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि इसका काम और इसकी पब्लिक की सेवाएं बहुत अच्छी हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि यह विभाग जिस तरह से लोगों को परेशानियों में डालता है वह एक अजीब सी बात है जिसके ऊपर मंत्रिमंडल को ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से सरकार की कोई नीति दूसरे विभागों में नहीं है उसी तरह से हम इस विभाग में भी देखते हैं कि सरकार की कोई नीति नहीं है। सरकार के शिक्षा विभाग को देखिए, सरकार के कृषि मंत्रालय को देखिये, सरकार के गृह विभाग को देखिये, जिस तरह से इन विभागों में कोई नीति नहीं है इसी तरह से इस विभाग में भी कोई नीति नहीं है।

मुख्य रूप से जो नीति होनी चाहिए वह यह कि डाक तार विभाग के कर्मचारियों के के लिए सुविधायें और इस तरह के हालात पैदा करना जिससे देश का अधिक से अधिक सेवा कर सकें और दूसरी नीति यह होनी चाहिए कि देश के तमाम भागों को इन की सेवाएं अधिक से अधिक प्राप्त हों। जहां तक जनता की सेवा का सवाल है अभी पिछले दिनों तीन चार दिन हुए इसी सदन के भूतपूर्व सदस्य माननीय श्री मंजू लाल जी द्विवेदी मिले थे और उन्होंने वह खत दिखलाया जो कि उस जमाने में लिखा गया था जब कांस्टीट्यूएंट असेम्बली के वह सदस्य थे और वह अब एक हफ्ता पहले उनको मिला है.....

एक माननीय सदस्य : मिल गया ?

श्री सरजू पाण्डेय : मिला 20 साल के बाद।

एक मजे शिकायत मिली है। आसनसोल के डाकखाने से 500 रुपया मनीआर्डर किया गया 1965 में। दो वर्ष हो गये लगातार विभाग को लिखते लिखते। मैं ने मंत्री जी को भी लिखा तो जैसी कि मंत्रियों की आदत है उत्तर देने की कि आपका पत्र मिला। धन्यवाद। कार्यवाही हो रही है। वैसा ही उत्तर मिल गया और मैं समझता हूं कि पूरे पांच वर्ष हो जायेंगे मगर उस मनीआर्डर का पता नहीं चलेगा कि वह रुपया क्या हुआ। इस तरह की सैकड़ों शिकायतें हैं।

टेलीफोन करते बैठिये, वहां के आपरेटर जो होते हैं काम नहीं करते। लगातार कई कई घंटे लोगों को बैठाये रहते हैं। पता नहीं चलता कि कहां क्या हो रहा है। मुझे मालूम हुआ है इलाहाबाद में एक टेलीफोन के अफसर हैं वह कई कई दिन तक दफ्तर ही नहीं आते हैं। और जब कभी आते हैं तो तीन चार सेर बकरे का मांस पकवाकर दफ्तर में ही खाते हैं। पिछले दिनों भारत अखबार में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि तीन चार सेर बकरे का गोश्त वही खाते हैं और तीन चार नौकर हमेशा उनकी सेवा मे रहते हैं। माननीय मंत्री जी को शर्म नही आती मुस्कराते हैं। हम को मालूम है कि वह भ्रष्ट अधिकारी है और तमाम रुपया खा रहा है। मंत्री महोदय का ध्यान उस तरफ दिलाया गया अखबार की कटिंग के द्वारा मगर उस पर कोई कार्यवाही नही हुई। मैं जानता हूं कि यह सरकार करना क्या चाहती है? उनके अफसर बैठे रहते है। कोई काम नही करते। जनता की सेवा नही करते। इनके लिए बड़ा बड़ा ... ... ती हैं। ... विभाग मे भी ... है। रेलवे बोर्ड ... ऐंड टी० डिपार्टमेंट का बड़ा ... बोर्ड है जिस में बड़े बड़े म...मच्छ बैठे हुए हैं, पूरा ... और जनता का, देश की कोई सेवा नही कर रहे हैं। जो छोटे छोटे एम्प्लायी हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नही है। मेरे हाथ में नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्ट ऐंड टेलीग्राफ एम्प्लायीज यूनियन का डिमांड है। इसमे उनकी सारी डिमांड ... हुई है। पूरा एक चार्ट है। अगर मै पढूंगा तो काफी समय लगेगा। आप चाहे तो देख सकते है। कर्मचारियो के रहने के लिए क्वार्टर्स नही हैं। अहमदाबाद में आर० एम० एस० के क्वार्टर्स चाहिए 7840 और कुल 4 हजार क्वार्टर्स हैं। बाकी ... हजार बगैर क्वार्टर के पड़े हैं। इसी तरह से दूसरी और बातें हैं जिन की बहुत लम्बी लिस्ट है। साधारण कर्मचारियो के लिए रहने की जगह नहीं है। इसी तरह से और दूसरी सुविधाएं इन को सरकार नहीं देती। इनके ट्रांसफर में तरह तरह की परेशानियां होती हैं जिससे काम मफर करता है। अगर उनको सही तौर पर सुविधाएं दी जातीं जो कि सही मानों में काम करने वाले हैं, आर० एम० एस० के छोटे छोटे कर्मचारी हैं, तो वह ज्यादा अच्छा काम करते। बदकिस्मती यह है कि यह बड़े बड़े मगरमच्छ जो बैठे हैं यह सारा रुपया खा जाते हैं और बेचारे छोटे छोटे कर्मचारी अगर मांग करते हैं तो डंडे से पीटे जाते हैं। फिर सरकार यह कहती है कि कम्युनिस्टों ने इनको बहका दिया जब कि सही मानो मे गरीब एम्प्लायीज के ऊपर सरकार ध्यान नही देती। अभी मुझे मालूम हुआ कि मंत्री जी ने स्वयं इस यूनियन के लोगो से बात की। इस यूनियन के लोगों का कहना था कि ओवरसीज टेलीग्राफ कम्यूनिकेशन के कर्मचारियो के बराबर हमारी भी तनख्वाहें होनी चाहिए। और बहुत सी मांगे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक आदमी को नियुक्त करेंगे आर्बिट्रेशन के लिए। कितना समय बीत गया? आदमी भी सजस्ट किया लेकिन उनका मामला नही भेजा गया।

12.23 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

तो काम करने के लिए बहतर हालात पैदा किए जायें जिस मे आदमी ईमानदारी से और अच्छाई से काम कर सकें। उस की ओर मंत्री जी का ध्यान नही है। पता नही मंत्री जी को मालूम है या नही, आज भी छोटे छोटे कर्मचारी मजबूर हैं गांव के लोगो से पैसे लेने के लिए। मनीआर्डर जब गांव में आता है तो एक आना फी रुपया उनका बंधा होता है। अगर कोई नही देता है तो उसका रुपया वापस हो जाता है। इसी तरह और लाखो किस्म की छोटी छोटी परेशानियां हैं। इसके लिए एक कारण यह है कि सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए वह हालत पैदा

[श्री सरजू पांडेय]

किए जिससे वह सही तरीके से काम कर सकें। सरकार न उनको मांगों पर ध्यान देती है न उनकी तनख्वाहों पर ध्यान देती है न और सुविधाओं पर ध्यान देती है। विभाग में जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं वह सारा रुपया खा जाते है। उन छोटे छोटे कर्मचारियो की तरफ कोई ध्यान नही देता।

अभी मुझे मालूम हुआ कि दिल्ली के अन्दर पोस्ट ऐंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के 14 सौ आदमी हैं। चार सौ से बढ़ कर 14 सौ आदमी हो गए लेकिन उनके रहने के लिए कोई स्थान नही दिलाया गया। आज भी वह एम्प्लायीज उसी तरह पड़े हुए हैं। क्या करे? कहा जायें? तो ऐसी हालत में जो रहेगा वह देश का क्या काम करेगा और जनता की क्या सेवा करेगा? यह बात हमारी समझ में नहीं आती।

इसी तरह से कानपुर में भी मुझे मालूम हुआ आर० एम० एस० के कर्मचारी है उनके लिए कोई सुविधा नही है। न रहने के लिए घर है न और कोई सुविधा दी गई है। तो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो वादा करो उसको पूरा करो। अव्वल तो हा हा करने की इन लोगो की आदत है लेकिन जब लड़ाई होती है पब्लिक का काम सफर करता है, लोग परेशान होते हैं तो डंडे से दबाना चाहते हैं। मगर मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि आज के जमाने में डंडे से काम नही चल सकता। हड़ताल होंगी अगर उनकी सही मागों पर ध्यान नही दिया जायेगा। अगर एक तरफ लोग ऊंचे महलों में रहेंगे, चार चार, छः छः हजार तनख्वाहें पायेंगे और दूसरी तरफ एक आदमी सौ रुपये पर काम करेगा तो आपका समाजवाद कैसे चलेगा? आप तो बड़ी बड़ी घोषणायें करते हैं। जरा इस पर भी ध्यान दीजिए कि इन मगरमच्छों की तनख्वाह काटकर छोटे छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ाइये ताकि देश से वह उत्साह पैदा हो जाय जिस से अच्छी तरह काम कर सकें। लेकिन सिर्फ डर से या धमकी से काम चलाना चाहें तो मैं आपको यह बता दूं कि एक पुराना सिद्धान्त यह है कि दण्ड देने से अपराध नहीं रुकते। एक जमाना था जब यह आंख फोड़ने के बदले में आंखें फोड़ी गई, दांत तोड़ने के बदले दांत तोड़े गये, चोरी करने वालों के हाथ काटे गए, बाहें काटी गई यहा तक कि यूरप के देशो में पाकेटमारी के लिए फासी की सजाए दी गई और लोग ऐलान करके बुलाए जाते थे कि फला आदमी को पाकेटमारी के जुर्म मे फासी की सजा होगी, और उसी जगह जो लोग तमाशा देखने जाते थे, वहीं उनकी जेबें कटती थी। चाहे आप यूनियन को कितनी ही गालिया दे लेवें, दबाने की कितनी ही कोशिश करें और डंडे से भी पीटें लेकिन इस तरह से आप उनमे व्याप्त असन्तोष को दबा नहीं सकते हैं और इस समस्या का हल नही कर सकते हैं। अगर आप सही मायनो मे देश की सेवा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि संचार विभाग का काम कुशलतापूर्वक हो और उन की सर्विसिज से जनता को आराम व सहूलियत मिले लोगो को उनके खत आदि जल्दी समय से मिलें तो आपको वहा पर ऐसे हालात कायम करने चाहिए जिनसे कर्मचारी लोग अपना काम मन लगा कर मुस्तैदी से करें।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

श्री सरजू पाण्डेय: बस मैं एक दो मिनट मे अपनी बात समाप्त करे देता हूं विभाग में जो बड़े अफसर लोग हैं वह मोटी मोटी तनख्वाहे लेकर ऐश व आराम कर रहे हैं। मैं आपको बतलाऊं कि इलाहाबाद के टेलीफोन विभाग के एक बड़े अफसर हैं जो वहां मजे से खूब गोश्त खाते हैं बकरा पूरा खा जाते हैं लेकिन काम धाम वह कुछ भी नही करते। अब ऐसे आलसी और ऐश व

भ्रष्टाचार में पड़े हुए अफसरों के खिलाफ सरकार अगर कार्यवाही नहीं करेगी तो इम्प्लायीज को खुद लाचार होकर कार्यवाही करनी पड़ेगी और तब आप परेशान हो उठेंगे और कहेंगे कि देखिये यह छोटे कर्मचारी कानून तोड़ते हैं। इसलिए इधर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए। हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका एक पिछड़ा हुआ अविकसित और गरीब इलाका है। हालत यह है कि वहां मीलों तक कोई डाकखाना नहीं है। न उन इलाकों में टेलीफोन की व्यवस्था है और न ही कोई अन्य संचार साधन हैं। अब देखने में यह आता है कि जो मंत्री इस मंत्रालय में आता है वह पहले झट से अपने यहां डाइरेक्ट टेलीफोन लगा लेता है। पहले श्री त्यागी नारायण सिंह इस विभाग के मंत्री होते थे तो उन्होंने झट से पटना डायरेक्ट का लिंक कर लिया। अब डा० राम सुभग सिंह मंत्री हैं तो वह पटना के अलावा बिहार के और दो चार बड़े शहरों को टेलीफोन से डाइरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में सिर्फ लखनऊ आगरा और कानपुर के टेलीफोन से डायरेक्ट कनेक्शन यहां से किये गये हैं बाकी जिलों में ऐसी कोई डायरेक्ट डायलिंग की व्यवस्था नहीं है। मंत्री महोदय से मेरा कहना है कि उन्हें पिछड़े हुए इलाकों की तरफ ध्यान देना चाहिये। मेरा कहना है कि जो सब से ज्यादा गरीब, पिछड़े हुए और अविकसित क्षेत्र हैं उन इलाकों में संचार के साधन सुलभ करने की ओर पहले ध्यान दिया जाय ताकि वहां की जनता भी यह अनुभव कर सके कि हमारे देश में आजादी आई है और यह कि हम आजाद हैं।

उपाध्यक्ष महोदय मैं आपको ऐसे गांव दिखा सकता हूं जहां महीनों तक डाक नहीं पहुंचती है। वहां डाक की पहुंचाने व बांटने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूं कि पिछड़े हुए इलाकों में डाक की समुचित व्यवस्था की जाय।

जो विभागीय कर्मचारी हैं खास कर कम वेतन पाने वाले छोटे कर्मचारी उन की सुविधाओं की ओर ध्यान दिया जाय और उनकी मांगों पर मंत्री महोदय को सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। मंत्री महोदय को अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम जो आश्वासन उन्होंने दे रखे हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। मंत्री महोदय को इन मगरमच्छ महात्माओं से सचेत रहना चाहिए। यह मगरमच्छ इस पूरे देश को खाये जा रहे हैं रेलवे विभाग में रेलवे बोर्ड रूपी मगरमच्छ सारी रेलवे की आय को खाते चले जा रहे हैं और अगर मंत्री महोदय समय रहते न चेते तो पी० एंड टी० में भी जो मगरमच्छ मौजूद हैं वह इधर भी चट कर जायेंगे और इतना ही नहीं यह सरकार को भी खा जायेंगे। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह जरा गम्भीरता से इस विषय में सोचें और देश की आर्थिक अवस्था को सामने रखते हुए विशेष सतर्कता व सावधानी से अपने विभाग के काम को चलायें और जैसा मैंने कहा उन्हें विशेषकर छोटे कर्मचारियों को सुविधा देने व गरीब अविकसित व पिछड़े हुए इलाकों में संचार व्यवस्था सुलभ करने की ओर अपना ध्यान लगाना चाहिए।

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Mr. Deputy Speaker, I feel very happy when I am asked to speak on this Ministry, because it is a Ministry of the people, for the people and it is also presided over by a gentleman whom I may call as the man of the people. Therefore, I think that this is one of the few Ministries in the Government of India which reaches every hamlet, every home, every city every village and gives service to millions of people in this country. I wish other Ministries were also so extensive in the field of their work as this Ministry is. I wish that other Ministries also were so careful about the needs of the common man as this Ministry is.

When I look through the Report I find that during the year under review 5,890 million postal articles, 44.3

[Shri D. C. Sharma]

million telegrams and 58.1 million trunk calls were dealt with. The number of post offices rose from 9,60,895 to more than 19 lakhs and the number of telephones from 7,66,342 to 8,57,822. I think this is a very sizable record of work done and I think anybody can feel happy about registering this kind of progress in the services which are rendered to the people.

But India is a very big and vast country, inhabited by so many crores of people and whenever anyone of us goes to his constituency the first question that is put to him is this. "Can our extra departmental post office be upgraded to a branch post office" or "will it be possible to have this branch post office upgraded to a sub post office" and so on and so forth Every village in this country wants a post office, a hospital, a school and a panchayat ghar. So, I would say that the Government of India would be winning the hearts of the people and also enlisting their affection if they were to spend more money on the Ministry of Communications. I wish that the budget for this Ministry should be increased two-fold so that no village remains without a post office and no village remains without those services which we need very much in free India today.

I know that during the First, Second and Third Plan much good work has been done by this Ministry There is no doubt about it, but, as I have already said, the demands are so many and the fulfilment of them is not adequate to the number of calls made on this Ministry. Therefore, my first point is this. This is a Ministry which serves the common man, the illiterate and the highly educated, the officer, men, the ignorant men, the educated peon, orderly, class 1 and class 4 people Therefore, for making its services more widespread, the budget of this Ministry should be raised two-fold so that it can go to those places where it has not gone now. For instance, I know of some backward areas and, unfortunately, I represent some backward areas in my constituency. In those backward areas the postal conveniences are not as plentiful as they should be. At one time my constituency was known as Narod Jamal Singh. It is a backward area, always affected by floods. You will be surprised to hear that the constituency called Narod Jamal Singh had only a branch post office Whenever I have gone there, people have clamoured for having a sub post office. Therefore, while I want that all these cities should have as many services as possible—trunk-dialling, three postal deliveries every day, express letter service and telegraphic money order service—I would ask the hon. Minister to take a survey of the backward areas in this country and then try to do something for them so that the backward areas are at least supplied with those essential services which are needed by our countrymen.

Will that happen? I think it can happen. I think the Planning Commission may have already made a survey of the backward areas and if you look at the pigeon holes of the Planning Commission you will find some survey of the backward areas lying there After having done that, during the Fourth Plan the hon Minister should give post offices, branch post offices to those backward villages and backward areas.

I also want to submit to the hon Minister that these extra-departmental post offices are an anachronism. They are reminiscent of the British Empire. They are relics of colonialism. They are remnants which have been left behind by those persons who were at one time our masters. Extra-departmental post offices should be abolished and in their place

Mr. Deputy-Speaker: Only two minutes more.

Shri D. C. Sharma: How many minutes will you give me?

Mr. Deputy-Speaker: In all ten. I am giving you one or two minutes more

Shri D. C. Sharma: All right.

My third point is about the P&T Board. When the P&T Board was formed I welcomed it. I remember my hon. and esteemed friend, Dr. Subbarayan, piloting the Bill for the P&T Board. I used to call him my brother and he was very affectionate towards me. I revere his sacred memory.

This P&T Board, I should say, is neither fish nor flesh nor fowl. I would submit very respectfully that the P&T Board should be modelled on the Railway Board. It should become a real executive arm of the Ministry of Communications; it should become a real instrument for carrying out the policies of the Ministry. What I find is that it has no power It only has a kind of advisory capacity. It can only suggest and indicate things. It can only meet once a while—twice or three times a year—and can take some decisions which are not very relevant, very important or very valid.

Mr. Deputy-Speaker: Now the hon. Member's time is up.

Shri D. C. Sharma: One or two minutes more and I will sit down. I think, you are very hard upon me today. I am used to the hardness of people; therefore, I do not mind it.

My next point is that the lot of the employees of the Railway Mail Service should be improved They have to work under very exacting conditions. Now that the law and order situation in the country is not so helpful as it used to be, some of these Railway Mail Service men have to bear the brunt of those persons who are law breakers. You might have heard that some of them lost their lives and that they were dealt with in a way which was inhuman. I would, therefore, say that the RMS people, who have to do night duty and who are really the kingpin of the postal services, should be given better salaries, better amenities and better protection.

Now I want to say something about telephones because I telephone to you also sometimes. I must congratulate the Government of India for the excellent arrangements that they made for us when we were fighting our elections. I must say that the arrangements in the Punjab were such as could not be improved upon and we all felt very happy. But when you come to Delhi and when you go to some other city, you find that half the telephone calls that you get are for a wrong number, 25 per cent of the calls that you get are meant for some other person, 15 per cent of the calls that you get are for some person who is not living in Delhi but in some other place and only 10 per cent of the calls are real calls. I, therefore, think that the telephone service must be improved. That can be improved only if you have telephone exchanges in every sizable town which has a population of 10,000 people. Every town in India, which has a population of 8,000 to 10,000 people, must have a public call office and, at the same time, the telephone exchange in Delhi must be strengthened so far as the mechanism is concerned, so far as the telephone operators are concerned and so far as the amenities of life for these persons are concerned.

Moreover, I would say that so many persons come to me and say that some of the women are sometimes put on night duty. I would ask the hon. Minister not to have women on night duty.

The last point—and I would speak only one sentence—is that when I go to a place or a city, I see the building of a school and I feel happy; I see a temple, a mosque or a gurudwara and that thrills me; but whenever I go to a place and I find a new building put up for the post office, I feel happy that it is a symbol of modern and free India. But I would say that in addition to the building for the post office the hon. Minister should also have what you may call quarters for the people who work there. I think, he must make a survey of this also. He must have a phased programme so that all the postal employees, from the postman up to the postmaster, have

[Shri D. C. Sharma]

their own places to live in and can have all those amenities of life which you and I enjoy

श्री राम चरण (खुर्जा) उपाध्यक्ष महोदय, खत का मजमून जान जाते है लिफाफा देख कर। आजादी के बीस साल बाद और कांग्रेस की बीस सालो की हुकूमत को देखने के बाद हमे पता लग जाता है कि जब के हम डिपार्टमेंट मे आजादी मिलने से पहले एफिशिएन्सी थी लेकिन आजादी मिलने के बाद जसे और डिपार्टमेंट्स मे इनएफिशिएन्सी बढ गई है उसी तरह से इस पी० एन्ड टी० डिपार्टमेंट मे भी बढ़ गई है। इस मे जो इनएफिशिएन्सी बढ़ी है उस की वजह यह है कि जो हमारे यहां ब्यूरोक्रेटिक टाइप का ऐडमिनिस्ट्रेशन है उस मे आप आफिसर्स को फैसिलिटीज देते हैं, फर्स्ट क्लास ऐकोमोडेशन देते हैं। एयर कंडिशन्ड आफिसेज देते है, लेकिन एक पोस्टमैन जो सारे दिन घूमता है उसको खादी की वर्दी मिलती है। पहले उसको बढ़िया यूनिफार्म मिला करती थी लेकिन अब खादी की मिलती है, जिसको पहन कर वह डाक बाटता है। उस के पास कोई प्रोटेक्शन नही है। धूप और सर्दी से। पोस्टमैन को क्लास तीन कहा जाता है लेकिन उस को तन्ख्वाह दी जाती है वह 75 से 95 तक ही है जो कि क्लास 4 की है।

इसी तरह से आप के यहा वायरमैन होते हैं उन को भी क्लास 3 ट्रीट किया जाता है लेकिन स्केल आफ पे क्लास 4 का दिया जाता है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि अगर उन्हे क्लास 3 ट्रीट किया गया है तो कम से कम क्लास 3 का जो स्केल है 110 से 150 तक उसमें उनको रखना चाहिये या इस के बीच मे रखना चाहिए ताकि उसमे एक सम्मान पैदा हो कि उन्हें क्लास 3 का ग्रेड मिला है।

इस के अलावा जो आप के यहां एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट आफिसेज हैं, जो कि एक पुराना रिवाज चला आ रहा है, वह गाव मे खोले जाते हैं। उस पोस्ट आफिस में जो आदमी काम करता है उस को 30 रु० महीने मिला करते हैं। पहले भी इतने ही मिलते थे और अब जब कि महंगाई इतनी बढ गई है तब भी वही 30 रुपये मिल रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वह सारा वक्त काम में गुजारता है लेकिन उस को कोई बेनिफिट नही मिलता है। इस लिये मेरा अनुरोध है कि जिस तरह से महगाई बढ़ी है उसी तरह से 30 रुपये के बजाय उसकी तीन गुनी तनख्वाह उस को मिलनी चाहिये। अगर इतना न भी दें तो कम से कम 60 रुपया तक मिलना चाहिए।

Shri Sonavane (Pandharpur) It should be abolished, It should not be given new life

श्री राम चरण : कट्रेक्ट बेसिस पर उन्हे रख छोडा है। या तो उनको अबालिश कर दिया जाय या कम से कम तीन गुनी अथवा दो गुनी पे दी जाय जिससे वह कुछ अपना काम चला सके और गरीब किसानो और जो दूसरे देहात के अनपढ़ आदमी हैं वे उनकी चिट्ठिया पढ़ सके। मैं अर्ज करना चाहता हू कि उन लोगो को अच्छी पे दी जाये, ताकि वे देहात के अनपढ़ लोगो के मनीआर्डर और चिट्ठिया वगैरह लिख सकें।

एक कैटेगरी माली की है। इस विभाग से सब कर्मचारियो को यूनिफार्म दी जाती है, लेकिन उसको यूनिफार्म नही दी जाती है, हालाकि वह बेचारा मिट्टी मे काम करता है। आखिर उसने क्या गुनाह किया है। उस को यूनिफार्म दी जानी चाहिए।

चौकीदारो को छुट्टी नही मिलती है। मैं निवेदन करना चाहता हू कि जिस तरह रेलवे विभाग मे लीव रिजर्व बनाया हुआ है, उसी तरह पी० एण्ड टी० में भी छुट्टी के लिये आदमी रखे जायें।

यूनिफार्म में जरूर सुधार होना चाहिए, क्योंकि बाहर की यूनिफार्म रखने से खादी और ग्रामोद्योग कमीशन को तो फायदा हो सकता है लेकिन उससे पोस्टमैन का प्रेस्टेज नहीं बढ़ता है। वे लोग मजबूरी में इसको पहनते हैं। जो मार्डन टाइप के पोस्टमैन हैं, वे तो इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि रेलवेज की तरह पोस्टमैन का भी अच्छी क्वालिटी की ड्रिल प्रोवाइड की जाये, जिससे उनमें आत्म सम्मान की भावना बढ़े।

महंगाई भत्ते के सवाल को लेकर पी० एंड टी० डिपार्टमेंट में बड़ा असन्तोष फैला हुआ है। अफसरों को तो इसकी कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि जब उनका डी० ए० बढ़ता है, तो वह सेविंग एकाउंट में जाता है, लेकिन जब क्लास थ्री और फोर का डी० ए० बढ़ता है, तो उस से उन लोगों का रोटी का गुजारा चलता है। वे लोग आम तौर पर कर्ज लेकर काम चलाते हैं। अगर उनको डी० ए० मिल जाये, तो वे कर्ज से बच सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि आफिसर्ज का डी० ए० न बढ़ाया जाये और सिर्फ 400 रुपये से कम वेतन पाने वालों का वेतन बढ़ाया जाये। बल्कि अफसरों का डी० ए० काट कर नीचे के कर्मचारियों का डी० ए० बढ़ाया जाये।

ट्रंक-काल के रेट बढ़ाये जाने से लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि खुर्जा से बुलन्दशहर ग्यारह मील है और उसके ट्रंक-काल चार्जिज 1 रुपया 70 पैसे हैं, जब कि बस का किराया 1 रुपया 20 पैसे है। अगर पी० पी० काल करें, तो चार्जिज 2 रुपये 20 पैसे बन जाते हैं। इस तरह चार्जिज के बढ़ाये जाने से टेलीफोन के विस्तार में रुकावट पड़ती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि टेलीफोन से बात कर के ज्यादा पैसे क्यों दें, क्या न खुद ही बस से चले जायें। इस लिए पचास मील से नीचे के ट्रंक-काल चार्जिज एक और दो रुपये के बीच होने चाहिए, ताकि लोगों को टेलीफोन का इस्तेमाल करने की आदत बढ़े और रेवेन्यू में भी वृद्धि हो।

पहले क्लास फोर के कर्मचारियों के प्रोमोशन के लिए डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन हुआ करता था, जिसमें शिड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन भी मुकर्रर था इस प्रकार शिड्यूल्ड कास्ट्स के दो चार आदमियों का प्रामोशन हो जाता था। लेकिन अब शिड्यूल्ड कास्ट्स रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया है, ताकि सर्विसिज में उनका परसेंटेज कम हो जाये। क्लास 3 में शिड्यूल्ड कास्ट्स का रिजर्वेशन लगभग 8 परसेंट है। उसको पूरा न होने देने के लिये एडमिनिस्ट्रेशन ने डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के जरिये प्रोमोशन में रिजर्वेशन को खत्म कर दिया है। मैं चाहता हूं कि उस में शिड्यूल्ड कास्ट्स के रिजर्वेशन को रेस्टोर किया जाये, ताकि क्लास फोर के कर्मचारियों को कुछ उत्साह मिले और अगर उन्होंने हाई स्कूल या इन्टर पास किया है, तो उनको कुछ प्रोमोशन मिल सके।

पंजाब के टुकड़े करके पंजाब और हरियाणा के दो प्रदेश बना दिए गए हैं और हिमाचल प्रदेश को अलग कर दिया गया है, लेकिन पी० एंड टी० सर्कल को अभी तक अलग नहीं किया गया है। इस लिए तीनों स्टेट्स में अलग अलग सर्कल सेट-अप किये जायें।

श्रीमती जयाबेन शाह (अमरेली) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आप ने मुझे समय दिया। मैं कुछ डिफीकल्टीज की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहती हूं।

[श्रीमती जयाबेन शाह]

इस विभाग के द्वारा एक नई प्रथा आरम्भ की गई कि ट्रंक-काल के बिलों में शहर का नाम और डेट को एलिमिनेट कर दिया गया है। सारे देश में यह मांग की जा रही है कि नई प्रथा से लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है और इस लिए इस के बारे में विचार किया जाना चाहिए।

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : यह बात कल मान ली गई थी।

श्रीमती जयाबेन शाह : थैंक यू। यह सुन कर मुझे बड़ा आनन्द है। आज हमारे देश के देहाती लोगों में जागृति आ गई है और वे चाहते हैं कि उन के यहां पोस्ट आफ़िस टेलिग्राफ आफ़िस और टेलिफोन आदि की व्यवस्था हो, लेकिन इस सम्बन्ध में इमर्जेंसी का कारण पेश कर दिया जाता है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि पोस्ट आफ़िस का छोटा सा मकान बनाना कोई लक्सरी नहीं है। जब दूसरी बड़ी बड़ी इमारतें आदि बनाई जा रही हैं, तो फिर पी० एंड टी० विभाग में इमर्जेन्सी को बनाए रखने में कोई औचित्य नहीं है। इस को जल्दी से जल्दी उठा लिया जाना चाहिए।

जहां तक ट्रंक-काल्ज के बिलों का सम्बन्ध है, उन के पैसे तो सम्बद्ध स्थानों से वसूल कर लिये जाते हैं, लेकिन अगर किसी बिल में कोई भूल हो, तो उसका सुधार करने के लिये दिल्ली से लिखा-पढ़ी करनी पड़ती है। इस प्रकार अगर कुछ देर हो, इससे लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है।

श्री इ० कु० गुजराल : यह बात भी मान ली गई है।

श्रीमती जयाबेन शाह : केवल मान लेना ही काफ़ी नहीं है। डिपार्टमेंट को इसके अनुसार कार्य करने के लिए भी कहा जाना चाहिए।

जो डिवीजनल एडवाइजरी कमेटी और जोनल एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है, उन की पावर्ज बिल्कुल नहीं के बराबर हैं। अगर इन कमेटीज को बनाए रखना है, तो इनको ज्यादा पावर्ज दी जायें, वर्ना इनको खत्म कर दिया जाये। वर्तमान स्थिति में इनसे कोई फायदा नहीं है। मैं गुजरात की एडवाइजरी कमेटी में हूं। मेरा अनुभव है कि इस वक्त ये कमेटीज बेकार हैं। अगर इनको रखना है, तो इनको ज्यादा पावर्ज दी जाये, ताकि मेम्बर कुछ काम कर सकें।

पी० एंड टी० विभाग के कर्मचारियों के लिए मकान आदि सुविधाओं की जो मांग की जाती हैं, वह तो ठीक है, लेकिन इस विभाग को जनता की आवश्यकताएं पूरा करने की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आज यह विभाग देश के कोने कोने में फैला हुआ है। आज पहले की स्थिति नहीं है कि केवल बड़े बड़े शहरों में ही लोग पोस्ट आफ़िस और टेलीफ़ोन आदि की सुविधायें चाहते हैं। आज यह विभाग लोगों की मांगों के मुताबिक काम नहीं कर सकता है और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसके दिल में इसकी इच्छा भी नहीं है। पंचायती राज स्थापित होने के कारण गावों में काम बढ़ा है और वहां के लोग इस विभाग से कई प्रकार की सुविधा चाहते हैं। विभाग की ओर से कहा जाता है कि सामान नहीं है, इमर्जेन्सी है। कई के बहाने बनाये जाते हैं, लेकिन लोगों को सुविधायें नहीं दी जाती हैं। मैं प्रार्थना करना चाहती हूं कि इस सम्बन्ध में जो दिक्कतें और बाटलनेक्स हैं, उन को हटाया जाये और लोगों की मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये।

श्री यमुना प्रसाद मण्डल (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया, ताकि मैं संचार विभाग की मांगों और संचार सम्बन्धी समस्याओं के बारे में अपने विचार प्रकट कर सकूं। जैसा कि श्री डी० सी० शर्मा ने कहा है, इस विभाग के द्वारा इलैक्शन के दौरान बड़ा संतोषप्रद काम किया गया है। संचार विभाग के सब कर्मचारियों ने बड़े उत्साह और तत्परता से काम किया है। इस बारे में एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की गई है। उस पुस्तिका से सारी बातों का पता नहीं चलता है, लेकिन हम लोगो को और करोड़ो लोगो को. . .

Mr. Deputy-Speaker: He may resume his speech after Lunch.

13 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Four Minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

DEMANDS FOR GRANTS—contd.

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS—contd.

Mr. Deputy-Speaker: We shall now take up further consideration of the Demands for Grants under the control of the Department of Communications.

Shri Yamuna Prasad Mandal may now resume his speech.

श्री यमुना प्रसाद मण्डल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि गत वर्ष चतुर्थ आम निर्वाचन के समय जब जनता एक बहुत बड़े काम में जूझी हुई थी संचार विभाग के कार्यकर्ताओं ने बड़ी दृढ़ता से और बड़ी ईमानदारी से काम को निभाया और जहां प्रजातन्त्र की परिपक्वता की परीक्षा थी वहां संचार विभाग के कार्यकर्ताओं की भी बड़ी परीक्षा हुई। उसमें वे सफल निकले और केवल सफलता ही उन को नहीं मिली देश के बड़े बड़े लोगों और जनता ने यह दाद दी कि संचार विभाग के लोगों का काम बड़ा अच्छा रहा। इतना ही नहीं उन लोगों का यह 'मोटो' रहा है : "अहर्निशं सेवामहे।" जो दिन रात सेवा करने वाले हैं उनका यह केवल 'मोटो' ही नहीं है बल्कि वह सचमुच दिन रात अच्छे बुरे हर समय में जाड़े गर्मी बरसात हर मौसम में काम करते रहते हैं। परन्तु जो कार्यकर्तागण निम्न स्तर पर कार्य करते हैं उनकी दशा को देखेंगे तो पता लगेगा कि चतुर्थ श्रेणी के लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है। मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। भुवनेश्वर कांग्रेस के बाद आपने यह निश्चय किया था कि हम समाजवाद की ओर चलेंगे। समाजवाद की ओर जाने में पहले ऐसे निम्न वर्ग के लोगों की अवस्था को भी सुधारने की ओर आपने कुछ काम अवश्य किया है। लेकिन और बहुत काम करने की आवश्यकता है जिससे चतुर्थ श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के कार्यकर्ताओं को, सचार विभाग में कार्य करने वालों को और भी अधिक सुविधा मिले। अगर थोड़ी भी सुविधा उन को रहने की, कार्य करने की मिले तो वह और अच्छा काम कर सकते हैं। आपने एक भी अच्छा उच्च या उच्चतर विद्यालय उनके बच्चों के लिए नहीं खोला है। कुछ डिस्पेंसरियां औषधालय तो कहीं कहीं खोले हे मगर उच्च विद्यालयों के बारे में आप को ध्यान देना होगा। यह ठीक है राज्य सरकार यह काम कर रही है। शिक्षा का काम राज्य सरकार के ऊपर है। मगर आप की भी जवाबदेही है। जिस तरह आप रेलवे में देखते हैं रेलवे बोर्ड की तरफ से रेलवे के स्कूल्स खोले जाते हैं और हर तरह की सुविधाएं दी जाती हैं उसी तरह पी० एण्ड टी० बोर्ड की तरफ से भी संचार विभाग की ओर से भी उन लोगों के हितों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए जिन के हितों की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।

[श्री यमुना प्रसाद मण्डल]

मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो कम यूनियन बनाते हैं जो कम संगठन रखते हैं आपस में सरकार उनका ध्यान कम रखती है। अगर वे लोग ज्यादा जोरो की आवाज लगायें तो उनकी सुविधाओ की ओर ध्यान देंगे। यह बात सही है कि उन्हे और भी संगठन करना है। यदि वे और उनकी यूनियन्स मजबूत नही होगी उन की आवाज बुलन्द नही होगी तो फिर सरकार की तरफ से ध्यान भी उन्हे कम मिलेगा। पिछले बीस वर्षों मे बहुत कुछ हुआ है। मगर यह इतना विशाल देश है इतना महान् देश है और अभी हमे बहुत कुछ करना बाकी है। इसलिए मैं यह कह रहा हू।

कल गुजराल साहब राज्य मन्त्री सचार विभाग कह रहे थे कि दो परसेंट टलीफोन हम शहरो को देगे तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि आखिर साढे पाच लाख गावो के लोगो की तरफ भी उनका ध्यान जाना चाहिए। आपने एक्स्ट्रा-डिपार्टमेंटल पोस्ट आफिसेज खोले हैं। उसमे जो कार्यकर्त्ता रखे हैं वे पुराने लोग हैं। गाव के पुराने जो लोग है जिनका काफी आधिपत्य है आर्थिक रूप से आप उन्हे 30 रुपया देते है वह उसकी परवाह नही करते। केवल लोगो पर एक प्रभाव डालने के लिए वह डाक बाबू बने हुए हैं। वहा पर आप को एक नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आपका काम इतना बढता जा रहा है। एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट-आफिसेज आप खोलते जा रहे है बहुत शीघ्रता से खोलते जा रहे हैं। सारा देश देख रहा है कि यह एक शुभ लक्षण है। मगर जिन के हाथ मे वह काम देते है वह ठीक से कर नही सकते हैं। यह मैं नही कहता कि शत प्रतिशत लोग ऐसे ही है। मगर चूकि यह पुरानी परिपाटी है पुराने लोगो के जिम्मे आप ने यह काम दिया है वह जान बूझ कर गाव के लोगो के साथ इन्साफ नही करते। दस दस बीस बीस दिन तक मनीआर्डर के रुपया उनके पास रह जाता है। गरीब मजदूर जो बडे बडे शहरों में काम करते हैं व जो पैसा (एम० ओज) भेजते हैं वह पैसा (मनीआर्डर) भी ठीक समय पर उनके घर वालो को नही मिल सकता। वह आवाज भी नही उठा सकते क्योकि गाव के बड़े प्रभावशाली आदमी (डाक बाबू) के हाथ में वह काम है।

इसलिए मैं कह रहा था कि अर्बनाइजेशन होने की वजह से, शहरीकरण होने के कारण संचार की सारी सुविधाएं इधर ही मिलती हैं। गावो मे भी थोडी यह सुविधा अधिक दी जायगी और उसे सुधारा जायेगा तो गावो मे भी सचार की रोशनी आयेगी। मैं सचार विभाग के बडे मन्त्री तथा जो कांग्रेस के एक बडे नेता डा० राम सुभग सिंह हैं उनसे कहूगा कि सन् 1969 मे हम लोग गाधी शती मनाने जा रहे हैं तो यह विशेष कर गावो मे डाक व सचार आदि की सुविधा पहुचाने का एक खास प्रोग्राम हाथ मे लिया जाना चाहिए

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो रहा हैं।

श्री यमुना प्रसाद मण्डल : बस मैं एक, दो मिनट मे अपनी बात समाप्त कर रहा हू। मैं कह रहा था कि गावो मे पोस्ट आफिस की व्यवस्था करने की तरफ खास तौर पर मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिए। यह खुशी का विषय है कि आप ने कही कही पर यह व्यवस्था की है लेकिन जैसा कि प्रो० शर्मा जी ने कहा मैं बैकवर्ड एरियाज मे यह सुविधा सुलभ करने के लिए खास तौर से कहना चाहूगा। पिछडे क्षेत्रो मे संचार व्यवस्था की ओर विशेष कर ध्यान दिया जाय उदाहरणार्थ भारत-नैपाल सीमावर्ती क्षेत्र मे सचार की सुविधा विशेष कर प्रदान की जायें। आपने ऐसे 10–20 पोस्ट आफिसेज खोले अवश्य हैं मगर उनमे जो विभिन्न प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए वह मौजूद नही है। फण्ड्स की कमी है उसे हम लोग महसूस करते हैं लेकिन विदेशो से भी आप के कई तरह के

एग्रीमेंट्स (आर्थिक सहायता) हो रहे हैं और इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे पिछडे इलाकों की ओर अवश्य ध्यान दिया जाय।

सन् 1959 तक एयरमेल सर्विस की व्यवस्था थी और हवाई जहाज से सब तरफ पत्र आदि भेजे जाते थे और यह स्वर्गीय किदवाई साहब के जमाने की बात है। लेकिन उसके बाद हो सकता है ऐयरोड्रोम की गडबडी की वजह से या और किन्हीं कारणो से यह एयरमेल सर्विस का काम आपने छोड दिया और अभी आप केवल मद्रास, बम्बई और कलकत्ते आदि डाक ऐयर से भेजते हैं। वैसे अब तो अनेको बडे बडे शहरो मे ऐयरोड्रोमस की माकूल व्यवस्था हो गई है और आप यदि चाहे तो फिर से बडे पैमाने पर ऐयरमेल सर्विस चला सकते है ताकि ज्यादा नही तो कम से कम भारतवर्ष के विभिन्न राज्यो की 17-18 राजधानियो से यहां से ऐयरमेल सर्विस चालू हो जाय। इसके लिए यदि आवश्यकता समझे तो ऐयर इडिया मे आप एक ऐसा एग्रीमेंट कर ले ताकि शीघ्रता से हवाई जहाज से डाक भेजी जाये और ऐसा होने से एक-दिन के भीतर ही आप पटना से यहा डाक की डिलीवरी कर सकते हैं। यह एक ऐसा गम्भीर प्रश्न है कि आप को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए।

डिस्लोकेशन आफ पोस्टल कम्युनिकेशस के बारे मे मन्त्रालय की रिपोर्ट मे पेज 33 पर चर्चा की गई है। मन्त्रालय को उधर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए खास कर बाढ वाले क्षेत्रो मे। रिपोर्ट के 33वें पन्ने से उन स्टेशन्स के नाम दिये गये है जहा बाढ के कारण पोस्टल सर्विस मे बाधा उत्पन्न हुई है खास कर हमारे क्षेत्र मे डिस्लोकेशन बहुत होता है। हर साल रिपोर्ट मे उसकी चर्चा आती है कि वहा पर डिस्लोकेशन हो गया। इस डिस्लोकेशन को रोकने की आप की ओर से कोशिश होनी चाहिए क्योंकि प्रीवेंशन इज बेटर दैन क्योर।

मेरा मत है कि यह पी० एण्ड टी० बोर्ड एक आटोनमस बौडी होनी चाहिए और इस सदन के अधिकांश सदस्य चाहते हैं कि उसे काफी ताकत मिलनी चाहिए ताकि वह कुशलतापूर्वक और तेजी के साथ अपना काम अंजाम दे सके। रेलवे बोर्ड के बाद यह पी० एण्ड टी० बोर्ड का ही स्थान आता है और इसलिए इन सब बातो पर ध्यान रखना चाहिए ताकि देश में सचार व्यवस्था और द्रुतगति से आगे बढे।

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, जो रपट गये साल की मैंने पढी है पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ के कामकाज के बारे में उससे यह मालूम हुआ कि इस वक्त हमारे मुल्क मे करीबन 1 लाख पोस्ट आफिस हैं और 12500 टेलीग्राफ आफिस हैं। एक हमेशा की चालाकी हमारी सरकार आंकडेबाजी में जो चलाती है वह चालाकी की कोशिश पोस्ट आफिस के आकड़ों के बारे में भी इस रपट में करने में आई है। यह बताने में आया है कि हर एक 13 वर्गमील के लिए एक पोस्ट आफिस है हिन्दुस्तान मे और हर 4500 लोगो के लिए एक पोस्ट आफिस है। मैं समझता हू कि मन्त्री महोदय इस बात को इकार नही करेंगे कि जो 5 लाख देहात हैं, गाव हैं उन गावो मे से शायद करीब करीब तीन चौथाई गावो मे अभी तक कोई भी पोस्ट की सुविधा पहुच नही पाई है। कहीं तीन दिन मे एक बार पोस्टमैन पहुंच सकता है तो कही 7 दिन में एक बार पहुंच पाता है। ऐसी हालत में हमारे कई जिलो मे कई गावो में कई इलाको मे आज भी चल रही है। बम्बई जैसे शहर में 200 वर्गमील के ऐरिया मे यह हो सकता है कि 60-70 पोस्ट आफिस लगाये हो। थाना जिले में जहा आदिवासियों की काफी संख्या है, काफी ऐसे गाव हैं जहा किसान रहा करते हैं वहां 1000 वर्गमील के लिए या 2000 वर्गमील के लिए 20 पोस्ट आफिस हैं मगर जब उस का ऐवेज निकाल कर मुल्क

[श्री जार्ज फरनेन्डीज]

के सामने सरकार रखती है तब यह आंकड़े-बाजी रक्खी जाती है अर्थात् 13 वर्ग मील के लिए एक पोस्ट आफिस हो सकता है। इस जाल में फंसाने के काम में सरकार को कामयाबी मिलती है। यह बात नहीं भूली जानी चाहिए कि 20 साल की आजादी के बाद इस मुल्क के करोड़ों लोगों तक अभी तक पोस्ट आफिस की सुविधा ठीक ढंग से पहुंचाने में इस सरकार ने कामयाबी नहीं पाई है। मैं आज यह मांग सरकार से करना चाहूंगा कि साल भर में हो सकता है कि योजना पूरी न हो जाय लेकिन दो साल या तीन साल की कोई ऐसी योजना तत्काल बनने में आ जाय कि जिससे ऐसा कोई भी काम न रहे हिन्दुस्तान में जहां अगर पूरे वक्त के लिए खुला रखने वाला पोस्ट आफ़िस न हो लेकिन रोज एक घंटे या आध घंटे के लिए काम करने वाला पोस्ट आफिस बन जाय तो यह चीज असम्भव नहीं है क्योंकि मैं समझता हूं कि सरकार का कोई न कोई खाते का सम्बन्ध हिन्दुस्तान के 5 लाख गावों से जरूर हुआ करता है। जब सरकार का सम्बन्ध हर एक गाव से इस वक्त है तो मामला एक ही रह गया कि पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ़ डिपार्टमेंट को सरकार के उस डिपार्टमेंट से सम्बन्ध जोड़ना चाहिए कि जिससे हर एक गाव में पोस्ट आफिस के तत्काल खोलने की व्यवस्था करने में आ जाय। अगर पूरे वक्त काम करने वाले आदमी की किसी जगह आवश्यकता न हो तो कोई मन्दिर, मस्जिद या कोई स्कूल लेकर, ऐसी किसी भीगज ह पर जहा जिम्मेदार आदमी उस गाव के हो उनके जरिए यह पोस्ट आफिस का काम इन इलाको में जब तक आप एक पक्का पोस्ट आफिस नहीं बना सकते हैं तब तक इस तरह से किया जाय। यह एक ठोस सुझाव मुझे सरकार को पोस्ट आफिस के बारे में देना था।

अब यह टेलीफोंस वाला मामला है जो कि इससे ज्यादा गम्भीर है। गम्भीर इस दृष्टि से है चूंकि यह शहरी मामला है और रोज के व्यापार और व्यवसाय से इसका सम्बन्ध रहता है। पता नहीं कितने लाख लोगों का नाम अभी तक टेलीफोन के लिए वेटिंग लिस्ट में पड़ा है और वह नम्बर रोज बरोज बढ़ता जाता है। की योजना सरकार बनाती है इस मामले मे हमें ऐसा लगता है कि इसमे पूरा दिल लगा कर काम नहीं होता है।

भ्रष्टाचार इसका कारण हो सकता है। जितनी बड़ी और लम्बी वेटिंग लिस्ट रहेगी उतना ही ज्यादा अफसरों को पैसा खाने का मौका मिलता है। मन्त्री महोदय को जब मैं ऐसा कहता हू तो नाराज नहीं होना चाहिए क्योंकि यह पैसे वाला मामला जैसे मैंने कहा वहा पर चलता है। शहरो में आज अगर आप को टेलीफोन लेना हो तो हर जगह पर वह जो लगाने के लिए आयेगा वह तो घर को पहुच ही जाता है। जहां से देना होता है वहा से वह लगाने तक कई जगहों पर यह पैसे वाला मामला चलता रहता है। इस लिये हम को ऐसा ही लगता है कि शायद इस में भ्रष्टाचार का कोई सम्बन्ध हो, सरकार की तकलीफ का कम सम्बन्ध हो। लेकिन जो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज बंगलोर की है मैं नही समझ पाता कि इस कारखाने की पैदावार को बढ़ाने के लिये सरकार ने कोई ठोस योजना क्यों नही बनाई। सार्वजनिक क्षेत्र में जो कारखाने अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं उन में से इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज वाला कारखाना भी एक है। उस को आप और भी बढ़ा सकते हैं। उस में शायद 5 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई गई है। उस को बढ़ा कर 10 करोड़ भी किया जा सकता था। पिछले साल इस कारखाने मे करीब 1 करोड़ रु० की विदेशी

मुद्रा इस देश के लिये कमाई । जो कारखाना विदेशी मुद्रा कमाता है उस को टेलीफोन विभाग को और बढ़ाना चाहिये । इस में जो वायर वगैरह की जरूरत होती है, क्वावेल्स की जरूरत होती है, जिस को बाहर से आना पड़ता है उस का काम हो सकता था । इस कारखाने को बढ़ा कर देश के लिये जो टेलीफोन की सुविधा की आवश्यकता है उस की पूर्ति के लिये बहुत काम हो सकता था और विदेशी मुद्रा कमाने का काम भी उस के जरिये हो सकता था । लेकिन वह नहीं हुआ । जो पैसा लगाया जाता है वह कई ऐसे उद्योगों मे सार्वजनिक क्षेत्र में लगाया जाता है जहा कोई कमाई नही होती और सारा पैसा डूब जाता है । मंत्री महोदय को मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज के बारे में वह सोचें और इस के साथ साथ आज शहरों में जो टेलीफोन की तकलीफ है उस को दूर करने की दृष्टि से भी काम करें ।

टेलिफोन के सम्बन्ध में बोलते हुए मैं बम्बई की एक बात कहना चाहता हू । मैंने सुना है कि जो बम्बई के टेलिफोन के कर्मचारी हैं वह बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं उन के जो दफ्तर हैं—मैं टेलीफोन एक्सचेन्जेज की बात नही कह रहा हूं बल्कि जो उन के दफ्तर हैं—वह किराये के मकानो में शहर के कोने कोने में रखे गये हैं । उन मकानों को छोड कर एक मकान बनाया जाये जहा पर तमाम दफ्तरों को रक्खा जाये । वे लोग यह मांग बहुत दिनों से करते चले आ रहे हैं लेकिन इस की ओर कोई ध्यान नही दिया गया है । मैंने तो यह भी सुना है कि पोस्ट ऐंड टेलिग्राफ डिपार्टमेंट ने कोई जमीन खरीद कर रक्खी है मकान बनाने के लिये लेकिन अब तक वहां पर मकान नहीं बनाया गया है । जमीन रहते हुए भी दूसरे मकान किराये में लेने का आवश्यकता पड़ी हो सकता है कि उसका किराया भी काफी देना पड़ता हो । आप जानते हैं कि बम्बई शहर में जो भी मकान लेता है उस को चार पांच हजार रुपया पगड़ी का देना होता है । शायद पगड़ी वाला मामला इस में भी हो और किसी अफसर का सम्बन्ध भी इस में हो । मैं आरोप नही लगाना चाहता लेकिन मैं चाहता हूं कि बम्बई में कर्मचारियों की ओर से बहुत दिनों से जो मांग की जा रही है उसके बारे में आप सोचें और निर्णय भी लें ।

टेलिफोन की सुविधा के बारे में कहना चाहता हूं कि जैसे उस की सुविधा शहर में चाहिये वैसे ही देहातों में भी टेलीफोन की सुविधा होनी चाहिये ।

कम्यूनिकेशन्स डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है उस में मैंने एक बहुत ही दिलचस्प बात पढी । वह हिन्दुस्तानी टेलिप्रिंटर्स के बारे में है । यहां पर हिन्दुस्तानी टेलिप्रिंटर्स का कारखाना आज सात साल से चल रहा है । ओलिवेटी के साथ जो कि इटैलियन टेलिप्रिंटर्स की कम्पनी है उन का कोलेबोरेशन है और वह अच्छे ढंग से चल रहा है । टेलिप्रिंटर बनाने का जो काम हिन्दुस्तान की सरकार ने अपने हाथ में लिया है सात साल से वह चल रहा है । जब सरकार ने भाषा के बारे में नीति बना कर रक्खी है कि हिन्दुस्तान में हिन्दी को चलाना है तब मेरी समझ में नही आता कि अच्छे किस्म के हिन्दी टेलिप्रिंटर बनाने में सरकार को कौन सी दिक्कत है । हिन्दी अखबार हिन्दुस्तान मे अच्छे ढग से नही चल पाते है । मैं जानना हूं कि उस की क्या वजह है । उस की वजह यह है कि जो भी खबरे छपती हैं पी० टी० आई० की या यू० एन० आई० की वह अंग्रेजी टेलिप्रिंटर्स से छपती है । उस के बाद उन का अनुवाद करना पड़ता है तब कही वह जा कर हिन्दी में छप सकेगी । ऐसा करने में उन को तकलीफ होती है क्योंकि खबरें तो शाम को चलनी शुरू होती हैं और रात को एक बजे तक की खबरें छप कर पहुंच जाती हैं । अखबार वाले

[श्री जार्ज फरनेन्डीज]

5 बजे बाहर ले जाते हैं । लेकिन अगर अनुवाद करने बैठें तो 10 बजे के बाद ही खबरें मिल सकेंगी । यह मूल कारण है जिस से हमारे हिन्दी के अखबार ठीक ढंग से हिन्दुस्तान में नहीं छप पाते । मैं समझता हू कि इस की सारी जिम्मेवारी कम्यूनिकेशन्स मिनिस्टर साहब को लेनी चाहिये । वे हिन्दी के भक्त हैं । लेकिन अगर वे हिन्दुस्तानी टेलिप्रिंटर के इस काम को अच्छी तरह नहीं करते और ठीक वक्त पर नहीं करते कि हिन्दी टेलिप्रिंटर यहां बनाये जायें ताकि हिन्दी के अखबारों का सुधार हो सके तब तक यही बात चलती रहेगी कि लोग कहेंगे पढे लिखे लोग कि बिना अंग्रेजी का अखबार पढे हुए उन की समझ मे नही आता कि दुनिया मे क्या हो रहा है । मैं इस को तकलीफ नही मानता । जो अंग्रेजी समर्थक हैं वे इस तरह की बात को ले कर बहानेबाजी करते है। लेकिन यह समस्या हल होनी चाहिये ।

यह जो रिपोर्ट है उस के आखीर मे लिखा हुआ है कि पिछले साल टेलिप्रिंटर्स मे मालिक और मजदूरो के रिश्ते बहुत अच्छ रहे । 37 दिनो की हडताल रही सिटी अलाउंस के बारे मे । उस के सम्बन्ध मे लिखा है कि 37 दिनो के बाद मंत्रियो की मध्यस्थता की वजह से उस हडताल को बिना शर्त वापस ले लिया गया और बिना शर्त वापस लेने के बाद उन्हे 12½ रु० दे दिये गये । मेरी समझ मे नही आता यह कैसे सरकार और मजदूरो के रिश्ते अच्छे रहे है कि 37 दिन हडताल करने के बाद मध्यस्थता सरकार ने की और उस के बाद 12½ रु० दिये गये । पहले ही दे दिया होता तो 50–100 टेलिप्रिंटर और बन जाते । यही स्थिति सारे पोस्ट ऐंड टेलिग्राफ डिपार्टमेंट के बारे मे है ।

मैं जानता हू कि बम्बई शहर मे जब बारिश शुरू हुई तो पोस्टमैनो ने काम बन्द कर दिया था और कहा कि छतरी नही है, हम कैसे काम करें ? उन्हें यूनिफार्म नही दी गई । मैंने सुना है कि आर० एम० एस० के जो वाचमैन रहते हैं उन्हें केवल 75 रु० के लिये बारह घटे काम करना होता है । मजदूरो के वास्ते जो कायदे बने हुए हैं, मजदूरो के के वास्ते जो नीतिया बनी हुई है, और जो खुद आप की सरकार चाहती है कि निजी क्षेत्रो के मालिक अपने मजदूरो के साथ अच्छा बरताव करे, मैं चाहूगा सरकार भी और खास कर पोस्ट ऐंड टेलिग्राफ डिपार्टमेंट जिस मे सवा चार या पाच लाख कर्मचारी काम करते है, अपने कर्मचारियो के बारे मे वही नीतिया रक्खे और उन को वही सुविधाये देने के बारे मे सोचे । उन को मकान देने के बारे मे भी सोचे । ऐसा काम नही किया जाना चाहिये जैसे कहा गया था कि तीसरी पच वर्षीय योजना मे 5 हजार मकान बनवाये जायेंगे कर्मचारियो के लिये । लेकिन उन मे से शायद एक भी नही बना । रेलवे ने बम्बई शहर मे जो डेढ सौ या दो सौ मकान बनवाये थे वह वैसे ही खाली पडे हुए है । उन्हे भी नही दिया जा रहा है । मै चाहता हू कर्मचारियो के बारे मे जो नीति है उस का तत्काल सुधारने का काम मत्री महोदय करे ।

Shri Narendra Singh Mahida (Anand) I shall be very brief

I had seen the days of dak runners in our country and I have seen the present age when our air mail is being carried by planes We have made progress which can be compared with any other modern nation in the world

Letters and telegrams deliver good or bad news, and the whole community is affected by this service So, it is a very important service to the nation

On the whole, the Ministry has done quite well Even during the elections, tributes were paid for the efficiency of this service I will mention here for your information, that Mr Chagla, our present Minister of External Affairs,

has paid a very glowing tribute He has stated that "the arrangements made for reporting election results are such as any country in the world, however advanced, should be proud of" I fully join him in this tribute

Many telephone exchanges have also been opened, and I am proud to say that the telephone exchange at my native place of Chandod was opened in record time. Telephone directories have also been published in regional languages, and they are being welcomed

There is a shortage of inland letters, and I want the Minister to attend to this need

I have been pressing for a commemoration stamp of the late Sayajirao Gaekwad I was also instrumental in hammering at the ministry in the consultative committees for a stamp for the late Sardar Patel It was only after a lot of perseverence that the ministry had the stamp of Sardar Patel issued sometime back I say with the same emphasis again that the Maharaja Sayajirao of Gaekwad, though we may be against the princes in the modern days, had rendered valuable service to the afflicted Harijans long before Mahatma Gandhi thought of them, and Ambedkar's service is modelled on the late Sayajirao's work So, because he was a Maharaja he should not be neglected and we could at least pay a small tribute to his memory by issuing a stamp I very earnestly request the Minister that a stamp should be issued as early as possible in memory of the late Maharaja Sayajirao who was a nationalist and also a reformer in this country

There have been many delays in the delivery of postal articles like letters I can quote my own instance, and bring it to the notice of the hon Minister A letter posted by me in December, 1988 to my wife, to Delhi was delivered here on the 24th May, 1987 Another surprising example is this a letter which my daughter addressed to her husband to Khetri, district Jhunjhunu in Rajasthan went to London, and it was sent back from London So, this is also a proof of misdirection and delay in the delivery of letters

Mr. Deputy-Speaker: Did you pay any extra charge for it?

Shri Narendra Singh Mahida: Some polite lady from London sent it back here I did not pay, that lady had paid for the air-mail I do not understand how it all happened; but that she had sent the letter back from London with a covering letter is a fact I have the letter here It is very surprising how sometimes service is rendered by the postal authorities here!

I should also like to bring to the notice of the hon Minister an amazing case in Gujarat circle A building has been rented by the postal authorities at the monthly rental of Rs 800 at Ahmedabad

This Ministry is now proposing to rent a house whose rent is 25,000 a month! It is shocking I want the hon Minister to enquire fully into the case All-India Postal Employees' Union, Class III, Gujarat Circle, has complained to me in the matter and has written to the Finance Minister in this connection, too

There are various references in the audit report of the Posts and Telegraphs I refer particularly to pages 10 13 and 14 of the report and bring them to the attention of the hon Minister

Mr. Deputy-Speaker. The hon Member's time is up

Shri Narendra Singh Mahida: That is why I am not repeating what the auditors have written Lastly, I must pay a well-deserving tribute to the Minister of Communications, Dr Ram Subhag Singh, for doing a very human act One of the employees of the Posts and Telegraphs Department was ill at a height of 12,000 feet, at Kaza station, in Himachal Pradesh Mr D V Parat, a 40-year old wireless operator was ill with a heart attack.

[Shri Narendra Singh Mahida]

This gentleman was saved purely because of Dr Ram Subhag Singh's personal interest. He was airlifted by a special Air Force helicopter and brought to Chandigarh within a very short time. Although a sum of about Rs 10,000 was spent on this mission of mercy, I am quite sure that the House will agree that by spending Rs 10,000, a valuable human life was saved and for that, I pay my glowing tribute to Dr Ram Subhag Singh

Mr. Deputy-Speaker: Shri K M. Abraham. I request hon Members to use telegraphic language, since there are a number of hon Members waiting to speak I would like to accommodate as many as possible.

Shri K. M. Abraham (Kottayam) Sir, the posts and telegraphs department has been notorious for its inefficiency which has further deteriorated recently The top-heavy bureaucratic apparatus is primarily responsible for this sorry state of affairs

For efficiency there should be an adequate and contented staff The second requirement is that working and living conditions should be good The third requirement is that the tools with which work has to be carried on should be provided in time These things however, are totally missing today There is serious shortage of staff throughout Kerala and other parts of the country The P & T is dependent on railways, for providing buildings for mail office in the railway platforms It is dependent on the railways for construction, replacement and provision of mail-vans in railway trains The P & T in accordance with its need, approve and sanction the openmg of new sections by railway trains But the railways do not provide mail-vans, though years and years pass on

The P & T Board is experimenting all kinds of schemes of administrative changes or innovations which have totally failed to bring about improvement of the service

In RMS they have introduced the Regional Director Scheme, and created three zones This has resulted in bottlenecks and total dislocation of mail arrangements. The officers consume the whole month in tours and are not able to attend to any work. The staff unions have been pleading for abolition of the scheme but the administration is clinging to this useless and top-heavy scheme Similarly in the telephone department the RDT scheme also proved to be a white elephant The P & T Department has also been indulging in a spate of reorganization of the offices causing much dislocation and hardship to the staff by transferring them to outstations These reorganizations are being done not with any view to improve the efficiency or the functioning but on the advice of the Foreign Consultants who have laid this condition for the grant of aid or assistance The decentralisation of the Telephone Revenue Accounts offices has only impaired the smooth functioning of the respective offices and has brought much suffering to the staff

Despite huge expenditure the expectations of the public are not fulfilled. The people of Ernakullam and Cochin have not been provided automatic telephone system in spite of repeated representations Rural suburbs of Kottayam have to book a Trunk Call to contact Kottayam friends This handicap has not yet been removed The whole Udumbumchola taluk of Kottayam District has neither telegraph offices nor telephones

The P & T Board has failed to provide stationery, forms, seals, furniture, sorting cases, hand-trucks, motor vans, drill bags, etc It is surprising to note that in RMS throughout Kerala there is a shortage of 29 hand-trucks Unless these are provided it is obvious that the staff cannot work.

With regard to amenities the less said the better The RMS Rest House in Delhi is having insufficient accommodation In a room where seven officials should take rest, 10 to 12 officials are forced to take rest. In Amritsar there is shortage of accommodation so much so that half of the

staff have to wait outside till those who are resting quit the beds There is filth all around No fan is provided I am shocked to learn that there are no rest houses in Shornur and Erode for RMS employees

In the P & T offices cycle-sheds are not provided There is no recreation room or tiffin room in offices

The Government has rejected the claim for the grant of the special compensatory allowance for P & T employees who had to shift from one place to another The employees are very much dissatisfied with the attitude of the administration in refusing to extend the concessions to the staff of the offices which are decentralised

Though the P & T administration have opened departmental dispensaries, yet it is managed most shabbily Complaints have been lodged against P & T doctors at Patna and Nagpur but no attention is paid The construction of a departmental building and quarters for the staff has been very poor The department has not taken adequate initiative to have buildings of its own, which enables vested interests to mint money To cite one glaring instance, the office of the General Manager, Telephones, Bombay is at present split up and located in about eight buildings in distant and different localities All these are rented buildings and a sum of Rs 6 lakhs is incurred annually as expenditure on this count The irony and the climax is that the department has never chosen to take up the construction of buildings and avoid this huge expenditure even though a plot in Cadell Road, Bombay is in possession of the P & T department since 10 years or more I have received complaints from Cannanore, Shoranur, Olvakkot, Alwaye, Ernakullam and Cochin A D's, Thiruvalla, Kottayam and Calicut from my state that these towns badly require new building for RMS offices The staff also are being subject to much hardship due to shortage of accommodation The department has made no serious attempt to construct quarters for the staff even in major cities like Bangalore, Trivandrum, Calcutta, Cuttack, Lucknow etc., the rent charged for the quarters is also high and the employee is made to forego the House rent allowance also when he is in occupation of the departmental quarters When I went to Trichur I was surprised to find that no quarters are provided to P & T staff

Hence there is no wonder that the P & T department works inefficiently There is need for drastic changes in the entire set up of P & T department if the things are to improve in the near future

Shri K. Ananda Nambiar and Shri N Sreekantan Nair have moved the following cut motions

"Victimisation of the Telegraph Traffic Employees by treating sick leave supported by medical certificate as 'Dies Non'"

"Need to refer the upward revision of pay scales of telegraphists to arbitration"

"Need to remove 'show-cause notice' threat to withdraw the recognition of the AITTE (Class III) union"

These demands are also to be treated as very urgent

Shri B. N. Shastri (Lakhimpur) Sir, I rise to support the demands for grants of the Ministry of Communications This ministry has five subjects under its control, but I am sure the common people are mainly concerned with the P & T Department alone P & T are the greatest of all the services that the Government have rendered to the people, because it concerns all people of the country. The postal system has gone into the remotest parts of the country If anyone goes into the interior most part of our country, one will come across two things—a village primary school in a big village or in between 2 villages and an extra-departmental or experimental post office every three to four miles by the roadside There is no difficulty in identifying the village primary school for the simple fact that

[Shri B. N. Shastri.]

the most dilapidated house in the village is the school house and a tin box with an opening with a protruding lip as red as the lips of the modern society girls indicates the existence of a post office. But whatever might be the housing condition of these schools and post offices, the people attach the greatest sanctity to these two institutions. To my mind, it is the success of democracy. Prof. Laski says that success of democracy can be measured by the voluntary cooperation of the people in the schemes and projects of the Government. Therefore, I am of the opinion that the P & T Department has succeeded in bringing all the people under this democratic regime.

The P & T Department, rather the Communications Department, is a public utility department. Its success can be judged from the point of view of utility. But it has an element of commerce. That element should be allowed to play its role freely and effectively. It is highly regrettable that telephone bills are accumulating year after year and the amount is quite high. There should be an attempt to realise the accumulating amounts as otherwise the department cannot function effectively.

This department, besides serving the people in respect of communication, helps the Nation in other respects also. Besides the usual savings bank account, the post office sells different savings certificates and helps the Nation to tide over its financial difficulties. It goes to the credit of this department that all the post offices have rendered services to the people to the best of their ability. P&T Department is entrusted with the trust of the people and Government and it is gratifying to note that this department has proved worthy of the trust reposed in it. But it is not an easy job. There is a saying in Sanskrit:

"दुःख न्यासस्य रक्षण —

"It is painful to keep the trust." I have never heard of divulgence of any secrecy or running away of a postman with the mail bags. It goes to the credit of this department, in spite of so much corruption all over the country.

In the modern world, a country is judged whether it is advanced or backward from the postal system it maintains. The more a country is advanced, the better are the postal facilities there. Therefore, India should have made an all-out effort to modernise its postal facilities and its postal system. Otherwise, India cannot compete with other modern countries in all parts of the world. It is a common feature that year after year, there is increase in postal rates and telegram fees. We do not grudge it. But we expect that with the increase in postal rates and telegram fees efficiency and speed of the department will also increase. I have received a telegram yesterday delivered from the Delhi main office. It was received there on the 8th July at 8.20 A.M. It was delivered to me on 10th July at 11.30 A.M., *i.e.* after 50 hours of its receipt by the main office. This shows the efficiency of this department in Delhi.

Coming to my State, I beg to point out that Assam is backward in many respects and Assam is neglected in all respects. In total disregard of the wishes of the people, the PMG's office is located at Shillong, whereas Gauhati is the central place not only of the State of Assam, but it is convenient, and easily accessible from NEFA, Nagaland and Manipur. But, not for the benefit of the people, but for the benefit and comfort of the top officials of this department, the PMG's office has been located at Shillong, because Shillong is a hill station, with a cool climate all over the year, with panoramic views and scenic beauty. There the tossing wind touching the evergreen leaves of the tall pine trees over the hilltops creates murmuring sounds to the rhythmic tune of the flowing stream beneath. Surely the top officials of the postal department cannot be indifferent to such scenic beauty. It is therefore that the PMG's office is located at Shillong.

The postal department has been issuing commemorative stamps of the great sons and daughters of India.

But up till now not a single commemorative stamp has been issued of any person in Assam. Assam should not be neglected in this way. Though Assam lies in a far flung corner in the eastern-most part of the country, I want to sound a word of caution:

"तुषेणापि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तण्डुला:"

If the husk is taken away, the grain cannot grow. If Assam is neglected in this way, it will be difficult for the rest of India to grow from prosperity to prosperity. Therefore, in the interest of the nation, Assam should not be neglected in this way. Since the birth centenary of Lakshminath Bez Barua, an illustrious son of Assam, is going to be celebrated in the year 1968 I hope this department will seize this opportunity to issue a commemorative stamp in his memory.

So far as employment is concerned, there are about 5 lakhs or more employees in this department. But there is a feeling in Assam that full justice has not been done to the children of the soil. There is a feeling of disappointment among the youths of Assam that this department is a taboo for the youth of Assam and the avenue of employment in this department is sealed for them. I appeal to the Minister to look into this matter. I hope that full justice will be done to Assam in this respect. I would also like to suggest that a Member of Parliament or a Member of the State Legislature from Assam should be a permanent invitee to the selection committee or board for all appointments in this Department in Assam Circle. With these words, I support the Demands for Grants.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रालय ने अभी कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि पांच वर्षों बाद भारत मे कोई विश्वविद्यालय इस प्रकार का नहीं होगा जहां प्रादेशिक भाषायें शिक्षा का माध्यम न हो गई हों। गृह मंत्रालय ने भी अभी कुछ दिन पहले यह घोषणा की थी कि संघीय लोक सेवा आयोग में चौदह भाषाओं के माध्यम से परीक्षायें एक वर्ष के अन्दर प्रारम्भ हो जायेंगी। वित्त मंत्रालय ने भी लगभग अपना कार्य दोनों भाषाओं में प्रारम्भ कर दिया है। लेकिन बीस वर्ष के बाद अगर कोई मंत्रालय इस प्रकार का भारत में है जो कि अभी तक यह अनुभव करता है कि ब्रिटिश शासन ही भारत मे कार्य कर रहा है, स्वतन्त्रता भारत में नहीं आई है, तो वह केवल संचार मंत्रालय है जिस के मंत्री डा० राम सुभग सिंह हैं। डा० राम सुभग सिंह को यह जान कर दु:ख होगा कि जिस मंत्रालय के वे मंत्री हैं बीस वर्ष की स्वतन्त्रता के बाद भी उस मंत्रालय के जो इस प्रकार के प्रकाशन हैं जिन का जनता से सीधा सम्बन्ध है वहां हिन्दी का प्रयोग सर्वथा नहीं हो रहा है।

मेरे हाथ मे उन के मंत्रालय के छपे हुए दो लिफाफे हैं, एक एक्सप्रेस डिलिवरी का और एक सामान्य। बीस वर्ष के पश्चात् भी उन लिफाफों में एक भी अक्षर संविधान में स्वीकृत राजभाषा हिन्दी का नहीं आ पाया। मैं सरकारी कर्मचारियों के लिये हलकी भाषा का प्रयोग करने का प्राय: आदी नहीं हूं। लेकिन सरकारी मशीनरी बीस वर्ष पूर्व भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय निर्णयों के अगर इस प्रकार चट्टान बन कर अटकना चाहती है और राजभाषा के रथ को रोकना चाहती है तो वह दिन दूर नहीं है जिस दिन जनता को सामूहिक रूप में उन के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाना पड़ेगा।

इसी बात का दूसरा पहलू यह है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को यह आदेश दिया था कि अगर सन् 1965 के बाद अंग्रेजी का प्रयोग हो तो उस में यह रूप होना चाहिये कि ऊपर ऊपर हिन्दी को प्राथमिकता दी जायेगी और नीचे उस के बाद अंग्रेजी रहेगी। लेकिन आज भी डाक के टिकटों पर लिफाफों के ऊपर और दूसरे प्रकाशनों में हिन्दी नाम की चीज नहीं है। जहां कहीं हिन्दी नहीं आई है उनमे प्रथम स्थान संचार मंत्रालय का है। संविधान के अनुसार और गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

अभी तक राजभाषा को उस को अपना स्थान इस मंत्रालय में नहीं मिल पाया है। इसी बात का परिचय देते हुए मेरे मित्र श्री जार्ज फरनेन्डीज ने कहा था कि इसी मंत्रालय द्वारा जिस टेलिप्रिंटर के कारखाने को सात साल काम करते हो गये उस की अभी तक जो वार्षिक रिपोर्ट आई है उस में कहते हैं कि पिछले साल 2200 का लक्ष्य था लेकिन हम ने 2700 टेलिप्रिंटर बनाये हैं। डा० राम सुभग सिंह क्या अपने उत्तर में बतलायेंगे कि हिन्दी टेलिप्रिंटर्स की कितनी मांग उन के पास है। हिन्दी टेलिप्रिंटर बनने का लाभ केवल हिन्दी के समाचारपत्रों को ही नही होगा, हिन्दी टेलिप्रिंटर बनने का लाभ मराठी समाचारपत्रों को होने वाला है और गुजराती समाचारपत्रों को होने वाला है। सभी राज्यों के मुख्य मंत्री एक मत से इस बात का निश्चय कर चुके हैं कि देवनागरी को वैकल्पिक लिपि के रूप मे सारे देश मे चलाया जाये। लेकिन जब तक हिन्दी के टेलिप्रिंटर ही उपलब्ध नही होंगे तब तक किस प्रकार देवनागरी को एक सामान्य लिपि के रूप मे सारे देश में प्रचलित किया जा सकता है? मंत्रालय ने बड़ी चतुराई से इन शब्दों को रक्खा है अपनी रिपोर्ट में। उन्होंने लिखा है कि :

"लगभग एक वर्ष मे यह निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।" यह नहीं लिखा कि एक वर्ष के बाद हिन्दी टेलिप्रिंटर उपलब्ध होने लगेंगे। निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। अभिप्राय क्या है? अभी दो-तीन वर्ष और लगेंगे। क्या संचार मंत्रालय अंग्रेजी की अनिवार्यता इतनी समझता है कि बराबर दो तीन वर्ष तक अंग्रेजी के टेलिप्रिंटर इस देश में बनाने की आवश्यकता है? हिन्दी के टेलिप्रिंटर की आवश्यका ही नही है? भारतीय भाषाओं को, अथवा बंगला, तमिल, गुजराती और दूसरी भाषाओं को इस प्रकार के टेलिप्रिंटर्स की कोई आवश्यकता नही जब भारतीय भाषायें उभर रही हैं और अंग्रेजी भारत से जा रही है, ऐसे समय में केवल अंग्रेजी टेलिप्रिंटर बनते रहने की बात समझ नहीं आती।

दूसरी बात मैं विशेष रूप से जो कहना चाहता हूं कि वह यह कि मैं डा० राम सुभग सिंह को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गुड मार्निग और गुड आफ्टरनून को बदल कर नमस्कार शुरू करवा दिया। जो टेलिफोन आपरेटर्स एक्सचेंजों में काम करते हैं उन को बड़ी कठिनाई होती थी। सुबह में शाम तक उन्हें गुड मार्निग, गुड नून गुड आफ्टरनून और गुड ईवनिंग कहने के लिये घड़ी देखनी पड़ती थी। इस के लिये उन्होंने नमस्कार शब्द चलाया है ताकि प्रातःकाल से सायंकाल तक उन्हें शब्दों का परिवर्तन करने की आवश्यकता ही न पड़े। लेकिन मैंने डा० राम सुभग सिंह को एक पत्र लिखा था और उस में मैंने कहा था कि अगर आप ने यह परिवर्तन किया हैं तो कम से कम शब्द तो शुद्ध उच्चारण करें। अगर वह भारत से नही सीखना चाहते तो ब्रूश्चेव जिस समय भारत में आये तो हमारा राष्ट्रीय अभिवादन क्या होना चाहिये यह चीज उन्होने हमें सिखाई। उन्होंने सारे देश में नमस्ते का प्रचार किया। नमस्कार शब्द का अर्थ होता है अभिवादन करना और नमस्ते शब्द का अर्थ होता है मैं आप का अभिवादन करता हूं। इस लिये अगर शब्द लिया ही है तो नमस्ते लेना चाहिये। नमस्कार शब्द व्याकरण की दृष्टि से और भाषा शास्त्र की दृष्टि से अशुद्ध है, इस का ध्यान रक्खा जाना चाहिये।

जहां तक टेलिफोन का सम्बन्ध है, इस के लिये सुझाव के रूप मे मैं इतना ही कहना चाहता हू कि कम्प्लेन्ट्स के बारे में लोगो को बहुत शिकायतें हैं। और तो और पार्लियामेन्ट के मेम्बरों का टेलिफोन डेढ़-डेढ़ दिन तक खराब रहता है। बार-बार

बाद, शिकायतें करने पर भी वह ठीक होने नहीं पाता। यह तो पार्लियामेंट मेम्बरों का हाल है, जो साधारण व्यक्ति होंगे उन को कितनी कठिनाई होती होगी इस का अनुमान प्रासानी से लगाया जा सकता है ।

पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने टेलिफोन की बकाया राशि के लिये, जोकि करोड़ों रुपयों में है, संचार मंत्रालय से कहा है कि ऐसे उपाय बरते जायें जिस से यह करोड़ों रुपयों की राशि प्राप्त की जा सके और जो देश का जाता हुआ धन है उस को बचाया जा सके ।

ऐसी ही स्थिति पिछड़े क्षेत्रों के डाकखानों के सम्बन्ध में भी है। मेरे कई मित्रों ने सुझाव दिया कि केवल आय की दृष्टि से ही डाकखानों की स्थापना न हो बल्कि इस लिये कि राष्ट्र का ही एक भाग गरीब और पिछड़े हुये क्षेत्र है । वहां पर अधिक से अधिक मात्रा में तारघर और डाकखानों की स्थापना होनी चाहिये ।

आज तार सेवा इतनी निष्क्रिय होती चली जा रही है कि लोग अपने पत्र एक्सप्रेस डिलिवरी से भेजना ज्यादा पसन्द करते हैं बनिस्बत तार भेजने के । चिट्ठियां पहले पहुंच जाती हैं और तार बाद में पहुंचते हैं । जब मंत्री महोदय से शिकायत की जाती है तब इधर-उधर के जवाब दे दिये जाते हैं । मैंने तीन चार तार डाक तार बोर्ड के मेम्बर-मैन को भेजे । जब मैंने शिकायत की तो उत्तर आता है कि आप के पैसे वापस कर दिये जायेंगे । क्या यही उत्तर इस का होना चाहिये कि आप के पैसे वापस भेज दिए जायेंगे ? क्या यह डाक तार बोर्ड और संचार मंत्रालय की क्रियाशीलता का परिचायक है ?

मैं एक सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं । आप यह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप तथा अन्य राष्ट्रीय पुरुषों के पोस्टेज स्टैम्प निकाल रहे हैं । बहुत से निकाल भी चुके हैं लेकिन इस दिल्ली के साथ एक बहुत बड़ा इतिहास अमर शहीद स्वामि श्रद्धानन्द का लगा हुआ है जिन्होंने चांदनी चौक घंटाघर पर अंग्रेजों के सामने अपनी छाती खोल कर उन की संगीनों को चुनौती दी थी । मेरा अनुरोध है कि स्वामी श्रद्धानन्द का पोस्टेज स्टैम्प भी जारी किया जाये ।

श्री नाथू राम अहिरवार (टीकमगढ): उपाध्यक्ष महोदय, मैं डाक तार विभाग की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मुझे इस विभाग का करीब 12 साल का अनुभव है और डाक तार विभाग के कर्मचारियों की जो तकलीफें है उनका भी मुझे पूरी तरह से अनुभव है । जब पोस्टमैन कड़कड़ाती हुई सर्दी और तेज धूप में अपने ऊपर आठ दस किलो का गट्ठर बांध कर पार्सल और चिट्ठियां लेकर दौड़ता है तब सब लोग खस की टट्टियों में बैठे होते हैं और बेचारा वह दरवाजे खटखटाता है । वह जनता की जो सेवा करता है उस सेवा के बदले में उसे मिलता क्या है ? उन बेचारों के लिये बड़े-बड़े शहरों में रहने के लिये स्थान नहीं है । दो-दो तीन-तीन मील दूर वह रहते हैं और ड्यूटी देने के लिये भाग आते है । डाकखानों में जो सुबह की ड्यूटी होती है उसको स्प्लिट ड्यूटी कहते हैं । उसके लिये जब उसको छः बजे डाकखाने पहुंचना होता है तब उसे पांच बजे घर से निकलना पड़ता है । वह अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़ देता है । डाकखाने के बाबू और पैकर कड़कड़ाती सर्दी में घर से निकलते हैं जब कि सूरज सात बजे निकलता है । कुछ दिनों तक जाड़ों में तो बच्चों को पता ही नहीं चलता है जब तक इतवार नहीं आता कि उनके पिता जी घर में रहते हैं या नहीं । सुबह पांच बजे बच्चों को सोता छोड़ कर वह चले

[श्री लाबू राम अहिरवार]

जाते हैं। 11 बजे जब वह लौटते हैं तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं और शाम को जब वह घर पहुचते हैं तो बच्चे सोये हुए होते हैं। तो उनको तो जब तक इतवार नही आता है बच्चो को पता ही नही चलता है कि वास्तव में उनके पिता जी घर पर है या कही बाहर गये हैं।

15. hrs.

अध्यक्ष महोदय, रेलवे डिपार्टमेंट के सब जगह क्वार्टर्स बने हुए है लेकिन डाकखाने के कर्मचारियो के लिए कोई क्वार्टर की व्यवस्था नही है। कर्मचारियो की बात क्या कहे पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट आफिस के लिए जहा भी बिल्डिंग की जरूरत होती है किराये पर बिल्डिंग लेना पसन्द करता है। यह नही कि डाकखाने के काम की सुविधा की दृष्टि से अपनी तरफ से बिल्डिंग बनाये उसके बजाये जहा भी जैसी भी बिल्डिंग मिल जाये किराये पर ले लेंगे। चाहे उस मे खडे-खडे काम करना पडे तो खडे खडे ही करेंगे और किराया अदा करेंगे। इसलिए मै चाहूगा कि जहा जरूरत हो वहा किराये की बिल्डिंग न ले कर अपने पोस्ट आफिस भवन बनाये जाये और जो डिस्ट्रिक्ट हेड-क्वार्टर्स है वहा पर कर्मचारियो के लिए क्वार्टर बनाने की व्यवस्था की जाये।

अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन और तार विभाग का जहा तक सम्बन्ध है मै टेलीफोन के सम्बन्ध मे कहना चाहता हू अभी कई माननीय सदस्यो ने बताया है कि हम को अपनी आमदनी की दृष्टि से नही बल्कि जनता की सुविधा की दृष्टि से डाकखाने खोलने चाहिए क्योकि हमारा देश पिछडा देश है और यहा पर डाक की सुविधाए हम ने अभी बाद मे चालू की हैं और इसमें मध्य प्रदेश तो इतना पिछडा हुआ प्रदेश है कि जो कई रियासतो को मिला कर बना हुआ है। वहा पर बहुत लम्बा चौडा आदिवासी क्षेत्र फैला हुआ है जिसमे डाकखाने की सुविधा नही है। उसमे कुछ इलाका ऐसा है जैसे आगरा से ग्वालियर, झासी, दमोह, सागर, टीकमगढ़ और छतरपुर का यह पूरा का पूरा डकैत एरिया है। इनमे कई जगहो पर जो पुलिस स्टेशन है वहा पर टेलीफोन या तार की व्यवस्था नही है। डाके भी पड जाय तो तीन-तीन चार-चार दिन तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर खबर नही पहुचती है। उससे कई परेशानिया होती है। शासकीय काम मे और जनता के कामो मे भी कई प्रकार की असुविधाए होती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि माननीय मत्री जी आगामी योजना मे जहा पर भी ऐसे पिछडे इलाके है जो डकैतो से ग्रस्त एरिया है वहा टेलीफोन और तार से उसे सबधित कर दे।

अध्यक्ष महोदय, मै एक निवेदन और करना चाहता हू कि जैसे भोपाल से बीना तक टेलीफोन कनेक्शन है और टीकमगढ के लिए कानपुर मे होकर सम्बन्ध जोडना होता है इसलिए मै चाहूगा कि बीना का टीकमगढ से सम्बन्ध जोड दिया जाये जिससे टीकमगढ से भोपाल तक सीधा सम्बन्ध हो जाये। इसी तरह से टीकमगढ से जतारा तक टेलीफोन कनेक्शन है। जतारा को मऊरानीपुर और छतरपुर से जोड दिया जाये तो टीकमगढ-रीवा सीधा टेलीफोन सम्बन्ध हो जायेगा। इन्ही शब्दो के साथ मैं माग का समर्थन करता हू।

Shri B. K. Das Chowdhury (Cooch Behar) Mr Deputy-Speaker, Sir in a welfare state certain organisations, industries and basic services are managed and controlled by the State—rather nationalised in order to achieve maximum benefit for the maximum number of people at the minimum cost—and the Posts and Telegraphs Department is undoubtedly one of them It is strange to find that a maximum cost is being charged instead by the Department today for their articles and services—one paisa postcard is now priced six paise and so is the case with the other articles and services offered by the Post and Telegraphs Department Instead of serving the people at a minimum cost, we are told by the hon Minister of Finance in his Budget speech that even with such

high and exorbitant rates, the Posts and Telegraphs Department has been running at a loss. It is really difficult to understand the profit and loss business of the Posts and Telegraphs Department; more so when one goes through the budgetary allocations. It is seen from the Demand that an amount of Rs. 15.78 crores is paid to the General Fund by way of dividend, a little over Rs. 2 crores is appropriated to the Development Fund and Rs. 2 crores to the P & T Revenue Fund. So, the position is quite clear that the department as a whole does not show any semblance of loss; loss arises only when a huge amount of money of Rs. 15 crores and more is appropriated for dividend and other purposes. Probably that amount is charged by way of total capital charge or rather interest for the total capital outlay.

In spite of these huge dividend and other development and reserve funds, the Posts and Telegraphs Department as a whole is out to make a further profit of Rs. 3 crores for this year. According to the new revised rates of certain items, the department would receive an amount of Rs. 4.44 crores in a full year. If we are really out to achieve maximum benefit at a minimum cost then this increase in rates is not justified. Even in the course of normal business a businessman would not dare to charge interest or dividend for the total capital outlay for year after year and put on the people increased cost in each and every year. Again, the capital outlay has been accumulated over years and taken from the public by way of additional taxation. The people are made to bear more and more taxes by way of these increased rates for postal articles and services. This is absolutely a capitalist way of approach to balance the Budget and not in the least socialist which hon. Ministers often times go out to preach.

The Posts and Telegraphs Department does not take proper care to improve efficiency and thereby they do not pave the way to earn more profit. This is abundantly clear from the report on activities and also the Audit Report wherein it has been well stated in Chapter III page 7 of the Audit Report that "the collection of telephone revenue in respect of bills issued up to 31st March, 1966 are in arrears as to the extent of Rs. 6.11 crores as on the 1st July, 1966." Further, the department failed to do away with certain avoidable extra expenditure on cable lines, as a result of this the department had to bear an extra expenditure of Rs. 20,360. There is also lack of supervision in the execution of telephone expansion projects in which a capital expenditure of Rs. 52.22 crores was incurred in the telephone branch during the three years ending on the 31st March, 1966, and as a result, much of the potential income was lost to the department although highly salaried officers are getting special pays along with other fancy emoluments and allowances. I most humbly submit that the hon. Minister should take note of all these points and facts and take proper action against all those erring officers. This is another instance which justifies us in saying that by adopting efficiency measures the department can earn more profit and therefore the increase in postal rates is not required.

From the report on 'Activities', one finds that there are 4,98,067 employees of which 1,74,161 are extra-departmental employees. It is not easily understandable as to what made the department to keep more than one-third of their employees as extra departmental or rather as casual employees with pay ranges from Rs. 30 to Rs. 40 along with certain allowances. in any case the total of these emoluments does not exceed Rs. 50 or so. It is not easily understandable, even unimaginable, that a man working as extra-departmental employee can manage his livelihood along with his one, two or three dependents with such a scanty pay. There is a peculiar strangulation of departmental rules and procedures through which those unfortunate extra departmental employees are compelled to work. It is nothing but an attempt to rob Peter to

[Shri B K. Daschowdhury.]

pay Paul while the departmental officials are making merry of the cost of those unfortunate extra-departmental employees.

Further, their services are at the mercy of their immediate superior officers—sometimes inspectors and others—and more often than not they are being kicked out of employment against which these extra-departmental employees have nothing to say There are instances where even for ten years together they serve as extra-departmental employees but are not taken in any regular cadre I ask the hon Minister to look into these facts Are they not serving the department with satisfaction even at the cost of their blood? Are they not an integral part of the department? Are the departments not exploiting their poverty and their helplessness? May I ask the hon Minister how long this inhuman exploitation would continue? I request the hon Minister to examine their cases with sympathy, and I further submit that their services be recognised as regular employees

I must appreciate here the feeling of my hon friend, Mr Patel, who dwelt on the distress of the poorly paid employees in general They are not only half-fed and half-clad but they have many more legitimate grievances against the departments concerned

The advantages and privileges to which the Class IV employees are entitled, such as dress, footwear, umbrella, cycle allowance, etc, are not given to them in time, and whenever they are given, they are not in proper order These employees have to wait in long queues to get their medical bills cashed. I request that the hon Minister may consider all these facts and figures and consider giving them more dearness allowances in view of the dearness of the commodities. I also request that the pay and allowances of employees be given on the principle of need-based quantum and not on any artificial adjustment.

Mr. Deputy-Speaker: Mr Sonavane

Shri Nambiar (Tiruchirapalli) I want only three minutes.

Mr. Deputy-Speaker: He will get 1½ minutes, but a little later

Shri Sonavane (Pandharpur) I rise to support the Demands of the Department of Communications I am happy, the Ministry is headed by our hon. Dr Ram Subhag Singh who is handling this Ministry for the first time and I am sure that he will bring to bear his energy and new outlook on the subjects that are under his charge

I particularly want to bring to his pointed notice the difficulties in rural areas regarding posts and telegraphs The most antiquated mode of communication in posts and telegraphs in villages is that of runner-system The runner-system was in vogue before Independence and even after 20 years, we have not given up that system. We are in a cycle age as our late, revered Pandit Jawaharlal Nehru had said and even then, the runner is made to run with his bag for about five or ten miles from the Railway Station to the village, he is not given a cycle nor are the State Transport services, which are running on roads, made use of The plea is that loss is incurred and, therefore, the facility of upgrading the extra-departmental post offices is denied There are several villages where there are only extra-departmental post offices and these extra-departmental post offices serve the round-about villages, probably these villages without these extra-departmental post offices get delivery of letters after a day or two Therefore, my humble submission to the hon Minister is that he should abolish all these extra-departmental post offices and upgrade them to sub-offices. because in villages, in these post offices, there are no facilities for issuing telegrams, there is no full-time post-office, letters are not available throughout, in the postal savings bank, we can withdraw only upto Rs 20; there are no arrangements for express delivery letters, and so many facilities which are available in towns and cities are

not available there. Therefore, people living in rural areas, the agriculturists, cannot avail themselves of these facilities. Suppose, there is a case of emergency or a riot, the villagers residing in such areas cannot send a telegram or a telephone call to summon the Police for help during such emergencies; they have got to run on a cycle or send a messenger because the ST services operate at times once or twice a day. Therefore, it is of utmost importance that these extra-departmental post-offices should be upgraded and a lot of help should be given to the villagers. The cities are loaded with one facility after another, one mode of communication after another, but the rural areas are neglected. This scheme of things should stop and the hon. Minister should pay more attention to rural areas. As a case in point, I have been residing in my village for the last 7 or 8 years; even after sending representation to the hon. Minister and to the departmental secretaries, my village, which is 12 miles away from the Railway Station, has not yet got a sub-post-office; this is, in spite of a Member of Parliament residing there; with all the inconvenience, I get my letters sent by the Lok Sabha Secretariat after about a week and I am not able to send any telegram, nor can I receive any telegram; the telegram for me comes from a post-office 12 miles away. (*Interruption*).

Shri Nambiar: We will support him.

Shri Sonavane: Therefore, my request to the hon. Minister is that, with his rural background, with his rural bias, he should pay more attention and care to these rural areas and do his best in providing them with sub-post-offices. I wish him success in this sphere and say that we will judge his work by his care of the poor and the rural areas. I wish him success in this behalf.

Shri M. N. Reddy (Nizamabad): The time at my disposal is very short. I would like to invite the attention of the hon. Minister to section 9 of the Telegraph Act and such other sections in the various P&T Acts. You will be surprised to note, Sir that all these sections are the remnants of the previous regime which never considered or claimed itself a Welfare State. What has been done in those sections is that they have simply substituted 'Government' for 'Crown' wherever that word occurred. That is the attention this Government and the hon. Ministers have been successively paying to this!

Wherever the public utility and essential services like the P & T fail for any reason whatsoever in the discharge of their duties, the cost that was paid for the service should be refunded. This is what is done in Western countries, whether they claim themselves as a Welfare State or a Socialist State. This is the simplest thing that we can do in this country. That is, when you are not in a position to discharge your duties, when telegrams, including express telegrams, are delivered after many days, the amount that was paid should be refunded without any request, with good grace and regrets. There should not be any application or a request; just for one or two rupees nobody would waste his time and money and wait for the reply from that Department. No amount of counselling or debate in this House would rectify the things unless the Minister personally, with all earnestness and zeal, looks into all those small things, which do require rectification. The P & T Department is essentially a public utility department. Therefore, it should never be considered as a commercial undertaking where profit alone will be the incentive for efficient working. I am emphasising this point because the loss that is incurred now in the Postal Department is sought to be recovered or compensated for by the exorbitant charges on telegrams and telephones. Even after paying such exorbitant charges, we are not having that efficiency in the services which should be commensurate with the cost that we pay.

[Shri M. N Reddy.]

We always have the most unhappy experience of the delay in the booking of trunk calls. We wait anxiously for a long time finally to hear either that the line is out of order or that the call can be expected only after a few hours or the next day and so on That creates so much of disgust in users and, I can understand, what one would do if the operator or the person in charge happened to be before one, but it is remote control and one cannot do anything, and so in disgust often one puts off the receiver.

Therefore, I would submit that the services should be improved and the efficiency should be improved before the rates for these services are increased.

As regards the use of khadi in the P & T Department, I would submit that it is a big fraud on the public exchequer The sonner it is discontinued, the better it will be for the public exchequer Whatever justification may have been therefor it in the past, there is no justification for it now Perhaps, it is a measure only to encourage the Khadi Commission which is composed, as we all know, of discarded and disgrunt led Congressmen Therefore, khadi should be discontinued and in its place some handloom or other cheaper mill-made cloth can be utilised

Surely, I would commend and appreciate the efficiency of the Bangalore Telephone Industries and also the teleprinter industry. Wherever credit is due, we must certainly pay our compliments; these are making good profits and working very efficiently. Therefore, we should encourage such industries and invest more funds in them so that they not only earn foreign exchange but also supply the much-needed equipment for our telephone and telegraph departments.

Coming nearer home to the problems of my area, I would submit that I and many other friends had helped the P & T Department, although we were not supposed to help them, in acquiring a very valuable site, for a pittance, in Nizamabad proper in the fond hope that we would have an automatic telephone exchange there in the near future. It is a very valuable property, but it is not yet commissioned into use; an old building is there without any use, because in spite of the fact that the plans and estimates had been approved, neither the work has been let out nor has construction for an automatic telephone exchange started there. Without that building, it was stated that they could not have an automatic exchange, and without an automatic exchange there cannot be any improvement in the efficiency of the service. So, it is a vicious circle with which we are confronted there.

Apart from this, there is a telephone exchange at Armur and Bodhan, some 16 miles from Nizamabad, and both are linked to Nizamabad Town exchange. But, for 29 days in a month both the exchanges remain out of order, and yet they are not ashamed of collecting the rental; and they also charge the booking and cancellation charges, the PP charges and so on. Instead of improving the services there, they insist on the collections, I do not know for what reason I would appeal to the hon Minister to look into this.

There is an exchange approved and sanctioned in September, 1966 at Kisannagar near Nizamabad It is a very big township which has come up recently with an industrial estate, schools, hospitals and so on. But the work on the exchange has not been started there because I am told that they have no copper wire. I enquired at the Andhra Circle Office at Hyderabad and I was told that they had not received any copper wire for the line and that it was for us to raise the matter in Delhi and that they were helpless without copper wire. So, merely sanctioning plans without copper wire is of no use. If they do not have copper wire, let them not sanction the schemes at all. If they sanction a scheme and keep it pending

for a number of years without doing anything, but they simply give us statistics that so many work, have been sanctioned and so on, it is of no use, it is self-delusion.

Therefore, once again, I would appeal to the hon Minister that even at the cost of our exports, let us have more equipment for our internal use, and whatever projects or plans were sanctioned should be implemented at the earliest so that the people will have all the benefits of the amount that is invested.

Shri Nambiar (Tiruchirapalli): I only want to drive home the points mentioned in my cut motion Nos 74, 75 and 76.

Cut motion No. 74 deals with the victimisation of the telegraph traffic employees by creating sick leave supported by medical certificate as dies *non*. When I had raised this question, it was almost agreed to by the hon. Minister that there would be no victimisation But now that period is being treated as broken service or as dies *non*, even though they have got leave to their credit So, I would request that leave may be granted to them for that period.

Cut motion No 75 refers to the need to refer the upward revision of pay scales of telegraphists to arbitration. This was agreed to by the hon Minister when the question of their struggle was withdrawn The hon Minister said that it would be referred to an one-man tribunal My humble request to him today is to carry out that promise and put it before the tribunal consisting of one person

My third cut motion refers to the need to remove the show-cause-notice threat to withdraw the recognition of the AITTE (Class III) Union. There was a show-cause-notice issued at that time That may be withdrawn now, because everything is normal now. But that show-cause notice is still hanging there; that piece of paper is still there: let it be blown up by the hon. Minister by another letter from here. That is my humble submission.

Finally, I would say a word about the extra-departmental staff. Let him show some mercy on them. They may be treated on a par with the departmental employees. Let the hon. Minister's generosity prevail upon those poor men.

15.30 hrs.

[SHRI C. K BHATTACHARYYA *in the Chair*].

श्री ग्र० सि० सहगल : (बिलासपुर) सभापति जी मैं संचार विभाग के टेलीप्रिंटर्स के ऊपर अपने विचार रखना चाहता हू । जो रिपोर्ट है उसके देखने से मालूम होता है कि 31 दिसम्बर 1966 तक 5 314 टेलीप्रिंटर्स हमारे यहा है । उसमे से कुल 72 टेलीप्रिंटर्स देवनागरी की-बोर्ड के हैं । मैं आप के मार्फत मत्री जी से अर्ज करूं कि जब हम हिन्दी को अपनी राष्ट्रभाषा बना रहे हैं उस हालत मे जैसा कि मेरे मित्र ने अभी कहा है हमें ज्यादा से ज्यादा टेलीप्रिंटर्स हिन्दी भाषा मे देना अति आवश्यक प्रतीत होता है ।

अब मैं जहा से चुनकर आता हू उसके बारे मे कुछ कहना चाहूगा । पडरिया एक स्थान है बिलासपुर कास्टीटयूएंसी में । वहा और लोरमी मे किसी किस्म से भी पोस्ट-आफिस की व्यवस्था पूरे तौर से न होने के कारण वहा पर जो एग्जामिनेशंस होते है उनके लिये जो पेपर्स जाते हैं उन पेपर्स को भी दूसरी जगह से मुगेली से ले जाकर देना पडता है । रविशंकर विश्वविद्यालय का वह सेंटर बनाया गया है तो वहा पर पोस्ट आफिस की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे जितने भी पेपर्स जाते है वह उन लोगों को मिलें । उसी तरह से उसी कास्टीटयूएंसी में बलौदा एक स्टेट कास्टीटयूएंसी है । वहां जो पोस्ट आफिस आप रन कर रहे हैं उसको भी सब-पोस्ट आफिस के रूप में बना करके वहां पर टेलीफोन और तार की व्यवस्था पंडरिया लोरमी में की जानी चाहिए । उसी तरह से कटघोरा तहसील में और छुरी तथा दूसरी जगहों पर टेलीफोन

[श्री स॰ सि॰ सहगल]

की व्यवस्था नहीं है। यदि आप पंडरिया में ले जा कर टेलीफोन की व्यवस्था करते हैं जो कि काफी दूर मुंगेली की तहसील में है तो व्यापारिक दृष्टिकोण से या और दूसरी दृष्टि से डिपार्टमेंट यह कह सकता है कि शायद उससे फ़ायदा न हो लेकिन मैं कहूंगा कि आप वहा पर कुछ रोज के लिए व्यवस्था करें और व्यवस्था करने के बाद में उसको देखें।

इसके बाद मैं आप से यह कहूंगा कि पोस्टल इंश्योरेंस के लिए आप ने जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था के जरिये जो आप ने रेट आफ़ इंटरेस्ट 3 5 परसेंट था उसे 4.1 परसेंट जोकि टोटल इंटरेस्ट जो अर्निंग थी बैलेंसेज में आप के पोस्ट आफिस के इंश्योरेंस में उसको बढ़ाया है। मैं कहता हू कि इससे लोगों को फायदा होगा और लोग इसकी तरफ आये आयेंगे और वह इस तरफ ज्यादा डिपाजिट करेंगे। मैं चाहूंगा कि जो हमारे यहां के माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं उनको आप अपने मंत्रालय से एग्जामिन करायें।

राज्यों मे आपकी जो कमेटिया हैं हर एक स्टेट में आपकी कमेटिया हैं सेंटर्स आप ने बना दिये हैं उनमें आप ऐसे आदमियों को रखिये जोकि बराबर अच्छे तरीके से ठीक तरीके से उसमे बैठ सकते है। उन कमेटियो को आप ज्यादा अधिकार दीजिये ताकि वहा के लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनमें वह पूरी मदद कर सकते है। इन शब्दो के साथ मैं संचार विभाग के नियंत्रणाधीन अनुदानों का समर्थन करता हू।

Dr. Karni Singh (Bikaner). Mr Chairman, communications and speedy communications—are essential in any developing country like India. It is a matter of much regret that in spite of the fact that we have been independent for 20 years now, our communications are sadly lagging behind the rest of our development. It appears to me that we are trying to build a jet age India with a bullock-cart mind. Although I have no disrespect for the bullock cart—it is a very sturdy means of transport—no country can be developed if the communications do not keep pace with the prosperity of the country.

I feel that if we wish to put right the problems afflicting the posts and telegraphs department and the trunk service, it is not only necessary for us to request the Minister but we must also request the administrative services and our labour union leaders to do their bit, because all of them put together can only put the service right

I feel that in a country like India, faced as we are with Pakistan on the one side and China on the other, it is essential that our communications are speeded up. It must be essential not only for Government and the citizen but also for the military to be able to communicate between their border posts and their headquarters, admitted of course that they have their own means of communication. I am afraid that the trunk services in the country have completely deteriorated. If you pick up the receiver and dial for a trunk call from here to Bombay or Calcutta, you can very well spend the rest of your sitting by the telephone.

Shri S. Kandappan (Mettur): You can better take a car and go there.

Dr. Karni Singh: If you want to get through to border cities like Bikaner, Jodhpur or Jaisalmer, you will have to wait for two or three days and at the end might be told that the trunk call is out of service. We have approached the hon. Minister and his predecessor about this difficulty of communication with these border cities and the trouble that this has been causing us. The Minister has only just now told us that the cause of this is the theft of telegraph wires. I would like to tell the hon. Minister that we are all educated men in this House; he had better go and tell it to the marines!

The actual truth is that there is something basically wrong with the trunk services. If the Minister gives any assurance concerning the trunk service, I would like it to be remitted to the Committee on Assurances to deal with it so that if they assure us that the service would be restored within a month, it will in fact be restored within a month.

Now, the objectives of socialism has been proclaimed from the house-tops particularly by the Government. I would like to know how is it possible for a poor citizen to be able to contact his family when the cost of an urgent trunk call is prohitibive. A call from Delhi to Bombay costs half the salary of a poor man If he wants to get through an ordinary trunk call booking, there is no chance of getting through at all I hope Government will consider that at least ordinary bookings also should be given a certain amount of priority.

Coming to the question of the telegram service, my hon. friend just referred to the fact that a large number of ordinary telegrams now are sent by post. I think it is a matter of very great regret that in a country like India when we have a telegraph service, ordinary telegrams sent particularly by our poor brothers do not get through to destination except by post. Often our letters reach quicker than the telegrams. I hope Government will do something about this.

The point has also been made that in case a telegram is sent by post, the money should be refunded. I think this should be done *ipso facto*, automatically. The hon. Minister should tell us that in the case of all those telegrams sent by post, the money in excess of the 15 paise for postage will be refunded to the citizen who sends the telegram.

Shri I. K. Gujral: It is refunded automatically.

Dr. Karni Singh: It is not. Many of my telegrams were sent by post without any refund being made to me.

Shri Ranga (Srikakulam): You cannot get the money unless you spend more on correspondence.

Dr. Karni Singh: That is hardly a welfare society.

Briefly referring to the postal services, over the last number of years it has been my experience that at least 10 per cent of the mail just does not get through. Often we have to send letters in duplicate whenever there is anything important, to ensure that at least one of the copies gets through. If we are trying to develop a dynamic society, a country which is going to compare with the rest of the world, how on earth could we possibly achieve those results unless our telephones, mail and telegrams are speeded up? I hope that the hon. Minister will take us into confidence and tell us how he proposes to achieve those dynamic results so that India can progress further.

श्रीमती लक्ष्मी बाई : (मेडक) : सभापति महोदय मैं केवल 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगी । मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो पिछडे हुए ताल्लुके हैं जहा कि रेल व टलीफोन की व्यवस्था नही है । नारायणखेड और रामायणपेट ताल्लुको में न तो रेल है और न टेलीफोन है । एक्सेशस से करीब तीन महीने पेश्तर टलीफोन की बाबत मैं वहां के रीजनल आफिसर से बोली थी और कहा था कि यहा पर टलीफोन की व्यवस्था होनी चाहिए । जनरल मैनेजर ने कहा था कि टलीफोन लग जायगा और उसके लिए खम्भे आदि भी लगा दिये गये थे लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक भी वहां टेलीफोन की व्यवस्था नही हो पाई है । मेरी कांस्टीटयुएंसी में जैसा मैंने कहा न तो ट्रेन है और न टलीफोन की व्यवस्था है । मंत्रालय को इस ओर विशेष रूप से देखना चाहिए और बैकवर्ड एरिया में खास करके इस तरह की सुविधा की व्यवस्था करनी चाहिए ।

[श्रीमती लक्ष्मी बाई]

जहां तक ट्रंक कौल का सवाल है मुझे अफसोस के साथ यह चीज कहनी पड़ती है कि यहां बहनों को ट्रंक मिलता नहीं है। मैं इसके लिए 20-20 और 25-25 मर्तबा रिंग करते करते थक जाती हूं और जब तक मैं 20-25 रिंग बेकार न करूं ट्रंक नहीं मिल पाता है। लेकिन हैदराबाद में ऐसा नहीं है। हैदराबाद में मुझे ट्रंक कौल आसानी से मिल जाता है। वहां सम्बद्ध विभाग के कर्मचारी सब मुझे जानते हैं कि संसद सदस्या श्रीमती लक्ष्मीबाई टेलीफोन कर रही है और मुझे कनेक्शन मिल जाता है लेकिन यहां दिल्ली में मेरी कोई पर्वाह नहीं करता और वह लक्ष्मीबाई एम० पी० को कुछ नहीं गिनते और जैसा मैंने कहा इस तरह से मुझे यहां पर ट्रंक कौल करने के लिए परेशान होना पड़ता है। मिनिस्टर साहब को इस ओर देखना चाहिए। 6 बजे टेलीफोन करके देखिये आप को कोई दफ्तर में मिलता नहीं है। टाइम के वास्ते टेलीफोन करती हूं लेकिन 5 मिनट तक घंटी बजती रहती है कोई उसे उठा कर सुनने वाला नहीं होता है।

टेलीफोन विभाग के कर्मचारियों से हम लेडीज एम० पी० को काफी शिकायत रहती है क्योंकि यह लेडीज के साथ जैसा सभ्यतापूर्वक इन्हें पेश आना चाहिए वैसे पेश नहीं आते हैं। यहां भी हमारी बहनों को इन टेलीफोन वालों से शिकायत रहती है और वही हाल हैदराबाद में भी है। रात को 1-2 और 3-3 बजे यह टेलीफोन वाले डिस्टर्ब करते हैं सोते में हम लेडीज को परेशान करते हैं वे सताते हैं। मैं चाहूंगी कि मंत्री महोदय इसबारे में जांच करायें और यह चीज बन्द करायें। यही शिकायत गर्ल्स होस्टल वालों को है कि यह टेलीफोन विभाग के कर्मचारी टेलीफोन का गलत व बेजा इस्तेमाल इस तरह से रात में लड़कियों को सताने और परेशान करने में करते हैं। रात में उनकी नींद बेजा तौर पर डिस्टर्ब करते हैं और असभ्यतापूर्वक व्यवहार करते हैं। मुझे उनकी ओर से इस बारे में काफी शिकायतें मिली हैं और मुझ से उन्होंने मांग की है कि मैं यह मामला पार्लियामेंट में उठाऊं और मंत्री महोदय का ध्यान इस चीज की ओर दिलाऊं। वह कहती है कि इस तरह से तो टेलीफोन रखना बेकार ही नहीं बल्कि अच्छा खासा तकलीफदेह भी है।

एक और चीज जोकि हम लोगों को परेशान करने वाली है वह है इन पोस्टमैनों के विभिन्न ग्रुपों द्वारा अलग-अलग त्योहारों आदि पर बख्शीश की मांग। एक तो ऑर्डिनेरी डाक का पोस्टमैन होता है दूसरा एक्सप्रेस डेलीवरी वाला पोस्टमैन होता है और तार वाला चपड़ासी अलग होता है और यह जो अलग अलग इस तरह से हम लोगों के पास घर में आकर इनाम देने के लिए तंग करते हैं यह प्रैक्टिस बन्द होनी चाहिए। इस तरह से हर एक एम० पी० के घर में अलग अलग इन लोगों का इनाम के लिए आना ठीक चीज नहीं है और इस ओर मंत्रालय को ध्यान देकर यह चीज बंद करानी चाहिए।

Shri D. N. Deb (Angul) I rise to speak a few words on the Demands of the Department of Comunications. With the limited time I have at my disposal, I shall cover briefly only a few points.

In reply to a short notice question on 5th July, 1967 the Hon. Minister has admitted that a postal racket has been unearthed at Calcutta very recently I cite this just to show that everything is not going on well with the Ministry of Communications.

The Post and Telegraphs Department had earned admiration in the past for its services, but after 20 years of independence we have been observing that the efficiency in th administration has been deteriorating. There is no sanctity attached to the work of delivery of postal articles, letters and packets. The bookpost is the most unprotected thing. No one is sure if he can send anything by bookpost safely. Newspapers, calenders, diaries and interesting magazines are always pinched in transit.

We are told that with the rise in population and increase in the standard of literacy, the volume of postal work has abnormally increased, but the reinforcement in staff has not been made accordingly. I understand the number of postmen should have been increased, but this has not been done, and as a result even express delivery letters are not delivered in time

The condition of late delivery of telegrams is all the more irritating, and as for trunk calls, many members have already expressed their views, and yesterday the Hon Minister has also explained on some points regarding getting new trunk lines and so many others things So, I do not want to take any time on that particular point.

All this has been done in spite of the department of posts and telegraphs being considered a commercial department What is actually happening is that the department is being exploited by the Government to get more revenue, while no case is taken to improve the efficiency of the department The Hon. Finance Minister had proposed to increase the postal rates even in this budget This shows that this department is being utilised by the Government to balance its deficit

The report says on page 23

"Owing to the financial stringency the opening of new post offices suffered a set-back"

"With the opening of new post offices and increase in the number of delivery staff considerable progress has been made in providing better delivery facilities.. "

In spite of these things, 7,56,438 complaints have been received, and in my own State of Orissa, complaints have been to the tune of 12,000. And especially in the rural areas because of the way of delivery it is abnormally delayed.

The department of communications is also looking after the Indian Telephone Industries at Bangalore, and the teleprinter factory at Madras. Generally the performance in the public sector is not very satisfactory, and the telephone industry is no exception to that. Still, the report mentioned that during the year 1965-66 the telephone industry has earned a profit of Rs. 74 33 lakhs I am sure if the management was more efficient, this figure could have been increased, and there was also scope for earning foreign exchange. It is also in the report that orders for Rs 150 lakhs have been received from foreign countries This is very encouraging If greater attention is paid to the promotion of exports, the performance can be more impressive.

In conclusion, Sir, I wish to say a few words about the Hindustan Teleprinters The report mentions that an agreement is being entered into with some foreign collaborators to manufacture Hindi teleprinters. I wish to impress upon the Government that this work should be speeded up The Samachar Bharati is feeling a great handicap in doing its work of transmitting messages without Hindi teleprinters, and this will be a great help for transmission of Hindi messages.

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh) : I am grateful to Hon. Members who have participated in this debate. About two dozen Hon. Members have taken part, and most of them have generally appreciated the working of the Communications Ministry. Even those who have not, like my hon. friend Mr. Kandappan have also been very constructive

The communist member Mr. Sarjoo Pandey was somewhat harsh on the P & T Board members and some other officers, but he did not cite any instance which should be looked into by the department, which is run by the P & T Board. The one instance that was pointed out by him was about an officer of Allahabad, but he did not say what type of mischief he was doing. He also said that in 1959 a money order was sent from Asansol, I do remember about the letter which he wrote to me recently, and I asked him to produce the money order receipt but he has not

[Dr. Ram Subhag Singh.]

yet done that. He has in a way failed in producing relevant papers in that regard.

He said that a letter was written during Constituent Assembly days, and that letter was replied to only recently. I do not know what type of criticism he wanted to offer, because now he should appreciate that even old letters are being replied to.

I am greatly thankful to Shri D. C. Sharma, because he wanted that the budget should be virtually doubled if we want to render good service to the nation.

The service that is being rendered by this department is such that it virtually touches every nook and corner of India and virtual every family in India, because a soldier might be on the top of the hills in Ladakh or in Aijal or anywhere in Nagaland or NEFA or on the border of high Himalayas, but that border security or army personnel is looking for mail, and it is our military postal service personnel which provides that succour to him. Because they take interest in sending all the mails in time, and I would have liked that some of our Members should have gone and seen the working of the department. It is also a matter of great satisfaction that our overseas communication service is virtually connecting every nook and corner of the world with our coutry, and through radio photo service, Telex service, telephone service, it is also rendring service to our press people and it is good that Shri Prakash Vir Shastri and some other Hon. Members have pointed out, and the Hon. Member who preceded me pointed out to the Hindi teleprinters and I believe that my DMK friend will bear me out, because I do not want to do any injustice to any language in our country, even to the languages which are not provided in the Constitution; the languages which have got a place in the Constitution are somewhat better-placed, but those which have not been provided any place in the Constitution also have got to be looked after.

Shri S. Kandappan : Even the Tamil money order forms which had been in circulation, have now been stopped.

Dr. Ram Subhag Singh : There was time when he was speaking and obviously he forgot to point out that matter while he was speaking. He was only dwelling on the fact that there should not be bilinguism in the administration. But I did not do that. It was done by others, may be by Prof. Ranga because he was a member of the Constituent Assembly and the Constituent Assembly as a whole took the decision which we are faithfully carrying out. We will carry out that decision as faithfully as we can.

Shri S. Kandappan: Sir, he is sidetracking the issue. I was asking about the implication of it, and the expenditure.

Dr. Ram Subhag Singh: Now, I may point out the budgetary position, especially as Mr. D. C. Sharma had raised that point. In the budget estimates for 1967-68, the revenue receipts have been estimated at Rs. 182.62 crores. The realisation of the revenue during the closing months of the last year did not, however, come up to our expectations. If this trend continues, it is felt that revenue receipt during the current year will be about Rs. 177 crores. On the expenditure side, we have provided Rs. 175.65 crores as the gross expenditure, which include a sum of Rs. 3 crores as arrear contribution to Renewals Reserve Fund. We have also provided Rs. 1.62 crores as the arrear dividend for 1965-66. It is anticipated that there will be an additional expenditure of about Rs. 4 crores for the increased dearness allowance consequent on the recommendation of the Gajendragadkar Commission. If, however, the revenue does not come up to the budget amount of Rs. 182.62 crores, we may find it difficult to pay the arrear contribution of Rs. 3 crores to the Renewal Reserve Fund and also the arrear dividend of Rs. 1.62 crores, because the revised estimate for 1966-67 reveals a deficit of Rs. 8.5 crores and Rs. 5.9 crores respectively in the working of the postal and telegraph

branches. According to the budget estimate for 1967-68, the estimated deficit is expected to amount to Rs. 9.7 crores on the postal side and Rs. 3.9 crores on the telegraph side. Having regard to this deficit, the proposed revision of P & T tariff is only to the tune of Rs. 4.44 crores; the break-up is, postal tariff, Rs. 1.84 crores; telegraph tariff, Rs. 1.02 crores; telephone tariff, Rs. 1.58 crores.

Several Hon. Members, particularly Shri Shashi Ranjan and other friends pointed out the need for relief to small newspapers. I consider that as a very real point and we will sympathetically examine that, and it will be indicated during the discussion of the Finance Bill.

Shri S. Kandappan : What about the telephone arrears?

Dr. Ram Subhag Singh : I am coming to that. It is good that Shri Kandappan has pointed out that. The telephone arrear is a big amount, and I do not want to mince matters here, and I do admit that it is not a happy affair, but still, it is going down. On 1st July, 1965, he arrear was to the tune of Rs. 6.11 crores. On 1st October, 1966, it came down to Rs. 5.24 crores. On 1st January, 1967, it was Rs. 5.23 crores, and on 1st February, 1967, it came down to Rs. 5.13 crores. On 1st March, 1967, it came down to Rs. 4.94 crores. But this is in regard to the Delhi telephone district. The outstanding has also come down substantially. The three-months old arrears on 1st July, 1966 were Rs. 2.75 crores; this has come down to Rs. 2.6 crores on 1st May, 1967, because we have already taken suitable steps in regard to realising the arrears. But again, I respect the sentiments expressed here on the floor of the House, and I take this opportunity to tell this House that I have instructed our department that everybody who is in arrears particularly prior to 1st January, 1965, must be served with a registered notice that he should pay the arrears and that this process must be completed by 20th August—the serving of notice to each man and woman who is in arrears.

Shri Umanath (Pudukkottai): Private connections are cut off within 15 days or so, if arrears are not paid within that date. Why not the same principle be applied to other connections also?

Dr. Ram Subhag Singh : In respect of the post-1965 period, it is being done universally, but what I mentioned now was for the pre-1965 period. Here, in Delhi, there are over 63,000 telephones and virtually 50 per cent of them are in arrears. After that period, we shall have house-to-house check; there may be an Inspector for 2,000 telephones and he should contact them after serving the notice. I assure the House that either we will realise the arrears or we will disconnect all the telephone connections during this year, be it government telephone or a private telephone.

Shri S. Kundu (Balasore) : Are you simplifying the method of collecting the arrears?

Dr. Ram Subhag Singh : Not simplifying. This process which is in existence will continue. On top of that,—this is regarding old arrears which are accruing and crores of rupees are in arrears—with a view to realising them, I have introduced this new process.

Shri S. Kundu : What the Members said was that the arrears have multiplied due to the inefficiency of the department.

Dr. Ram Subhag Singh : I admit that. I had conceded that earlier.

Shri Jyotirmoy Basu (Diamond Harbour) : You can disconnect the subscriber who has not paid. But then, if the telephone remains ineffective for days together, has he got the right to smash the receiver? The service has gone to dogs.

Dr. Ram Subhag Singh : He always talks in terms of smashing. Those who know how to smash never talk about it. (*Interruption*).

Shri Jyotirmoy Basu : Read the Calcutta paper's editorial.

Dr. Ram Subhag Singh: I have read it. Reading is not your monopoly. I have read the Calcutta papers also.

Now, during the pre-Independence period, there were only 12,116 post-offices. Now, their number has gone to 97,000 and we propose to open new post-offices also during the fourth Five Year Plan. During the fourth plan, it is proposed to open 9500 post offices in rural areas and 2500 in urban areas. Mr. Fernandes said he calculated Bombay area also as an urban area. I do admit that postal facilities must be extended more and more in backward areas, hilly areas and jungle areas also and suitable postal facilities should be extended throughout the length and breadth of the country, be it at a loss also

16 hrs.

Mr. Sharma pointed out about survey of backward areas There has been some survey, but for refreshing our memory, I shall have that calculated on survey report basis also

With a view to increasing telecommunication facilities, we want to open a satellite communication service also. Steps are being taken to establish a ground station in India for participation in the global communication satellite system. The necessary land for the establishment of the ground station has been acquired at Arvi near Poona. It is hoped that the ground station will have been established by the latter half of 1968, by which time the Indian Ocean satellite is proposed to be launched The satellite over the Indian Ocean area, which will extend commercial capability to India and other areas in the region is expected to be launched in the latter half of 1968, by which time, the Indian ground station is proposed to be set up.

I have already referred to small newspapers, The service which they render to the nation is quite significant and therefore, we are going to consider whether we can do something to help them.

The rates that are there in the postal, telegraph and telephone systems were fixed on an ad hoc basis. I do not want that we should proceed on an ad hoc basis. Therefore, I feel that a suitable committee, consisting of officials and non-officials should be constituted to go into the entire tariff structure. If an expert committee gives advice, that will be a good guideline for us. We are soon going to constitute a tariff enquiry committee Its terms of reference will be

(a) To review the principles followed from time to time in fixing the rates and tariffs for different P & T services.

(b) To review procedure and the principles adopted to ascertain the cost of different services and suggest modifications, if any

(c) To review the economics of the various services provided, the extent to which the uneconomic services compete with those which are relatively more remunerative and suggest measures for preventing the diversion of traffic from the remunerative to the unremunerative services

(d) To evolve principles of tariffication keeping in mind the interests of trade and inoustry and at the same time taking into account the commercial character of the P & T Department.

(e) To examine whether it is necessary to provide special concessional rates to any class or classes of users or in respect of any particular services provided by the Department.

(f) To evolve principles for the expansion and extension of P & T facilities in new areas to meet public needs keeping in view the commercial character of the P & T services.

(g) To suggest any other measures considered necessary for improving the finances of the Department and making the services effective.

Mr. Singh Deo and some other Hon. Members referred to the need for reconstitution of the Board or making suitable modifications in its constitution. The House will be happy to know that we have already taken some steps in this regard. The position of the Member (Finance) *vis-a-vis* the P & T Board has recently been reviewed. This Member is now an officer of the Ministry of Finance. It has been decided to integrate the finance function with the P & T Board on lines similar to those obtaining in the Railway Board and this is being given effect to very shortly. Posts are being created for the Member (Finance) and his finance wing in the P & T Board It has also been decided to give the Member (Finance) functional responsibilities He will hereafter be in charge of Accounts and Budget in addition to Finance.

It is also intended to delegate enhanced financial powers to the P&T Board and to the P & T circles i.e PMGs, etc. so as to enable the cases to be disposed of more quickly at their level On the pattern in the railways, it has also been decided to transfer the function of the keeping of the accounts of the Telecommunications Branch of the P & T from the Department of the Comptroller and Auditor General to the P & T Board This change-over will be commenced this year and get completed over a five-year period The changes I have referred to will bring a greater measure of cohesion to the P & T Department A further examination of the structure of the Board will be made in the light of the recommendations which the Administrative Reforms Commission may make

Shri K. P. Singh Deo (Dhenkanal): What about the post of Director-General?

Dr. Ram Subhag Singh: As I said, I am waiting for the recommendations of the ARC My intention is to make it just on the basis of the Railway Board.

Shri Shashi Ranjan referred o the Delhi-Patna Muzaffarpur link and the repeater station at Bhagwanpur. Now it is being based on the micro-wave equipment. This micro-wave project is scheduled to be completed in 1968-69

Some envelopes were shown by Mr. Prakash Vir Shastri. I will soon have it changed to the standard be expects He also referred to Hindi teleprinters and wanted the number of Hindi teleprinters that are needed. I do admit as Mr Fernandes said, over the last 7 years this matter is under consideration. I will see that by next year our Hindustan Teleprinters Limited starts producing Hindi teleprinters also along with English teleprinters, so that we can meet the requirements of the Hindi newspapers and Marathi newspapers also

श्री प्रकाशवीर शास्त्री :अगले साल का मतलब क्या दिसम्बर सन् 1968 से है ?

डा० राम सुभग सिंह : जी नहीं अगर आप कहेंगे तो उसके पहले ही जुलाई से ही कर देंगे ।

Mr Singh Deo also spoke about the mail motor service for Dhenkanal and Kalahandi He will be happy to know that State transport buses are now utilised for conveyance of mail between Cuttack, Dhenkanal, Angul and Athamallick which has resulted in receipt of mails at Dhenkanal two hours earlier

Shri J. B. Kripalani (Guna): What about opening of private letters?

Dr. Ram Subhag Singh: That is wrong. But public men should not mind it

16-10 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*].

The post offices at Dhenkanal and Athmallick are housed in ex-State buildings The Department is negotiating with the State Government of Orissa for the purchase of these buildings

Shri N. N Patel pointed out that the head post office at Bulsar is functioning in two rented buildings. The construction of the departmental building has been entrusted to the Gujarat State

[Dr. Ram Subhag Singh.]

PWD. Administrative approval and expenditure sanction for a sum of Rs. 4.35 lakhs has been issued on 5th November, 1966. The detailed estimate is under preparation and we are pressing the State Government to commence construction of the building during this year.

Some Hon. Members referred to the shortage of forms and also inland letters. I am pained to find that even in a place like Varanasi there is shortage of inland letters. I will see to it that they are supplied in time. Regarding non-essential forms, they are printed in Government presses under the C.C.P.S. and we shall request the department concerned to print more forms.

Shri M. N. Reddy : In this connection, why do you not change the colour of the inland also It is very dull and drab.

Dr. Ram Subhag Singh : I am trying to change the colour of the inland and envelope and also their size. But the difficulty is that inland letters are printed at the Nasik Security Press and they are at the moment not ready to undertake that. Anyway, I will press them to do it.

Shri Sonavane pointed out some village post office. I hope that will be elevated to the position he wants.

Some hon. Members referred to the extra-departmental employees of the P. & T. The strength of the ED staff as on 31st March 1966 was 1,74,000, which is a big number. They are not required to work for more than five hours a day. Their remuneration is based on the recommendation of a departmental committee called Rajan Committee. They are now placed under various categories. Our attempt will be to see that they do not suffer any undue hardship.

Shri Nambiar: They should be brought on par with the regular employees.

Dr. Ram Subhag Singh: I have heard him patiently. He referred to the promise that I made. But if he had been attentive in Parliament and if he had perused the paper which I read out on the floor of the House and what my esteemed friend, Shri Gujral said yesterday, he would have found that I had not deviated from that. I honour every promise or statement I make here or elsewhere. If I have made any promise to anybody. I am going to adhere to that. I do not want any of our staff to be put to any difficulties or suffer because I have made a promise and did not implement it.

Shri S. Kundu: Let me make the Minister understand....

Dr. Ram Subhag Singh: He can ask questions later on; not now. I am not yielding at present.... (*Interruptions*) He can ask any number of questions later on.

Shri K. M. Abraham referred to the necessity of introducing automatic telephones in Ernakulam and Cochin. Cochin is already having an automatic exchange of 2,400 lines capacity. As on 31st March 1967 there are 1988 working connections and 139 in the waiting list.

Ernakulam is having at present a CB exchange of 2,200 lines capacity with 2,103 working connections and 1,373 in the waiting list as on 31st March 1967. A new building has been constructed for installation of automatic exchange. Equipment installation work is in progress and 3,000 lines are expected to be commenced during 1968. Equipment has also been ordered for extension of this capacity to 5,000 lines. Work on this extension will be taken up during 1968 and completed during 1969.

Shri M. N. Reddy: What about Nizamabad Automatic Exchange?

Dr. Ram Subhag Singh: There also the matter will be looked into.

Shri M. N. Reddy: What about Assam. It is very much in our mind. Not only Assam, but all the border areas around Saam should receive the highest consideration and priority. The

suggestions that he has made are most welcome. I will see to it that suitable postal and telephonic facilities are provided in those areas. He also referred to commemorative stamps That will be examined.

Some hon. Members referred to the need for improvement in the quality of service Shrimati Laxmi Bai said that whenever she lifts the telephone in Hyderabad people get afraid of her and they disconnect whereas in Delhi they do not listen at all. My attempt will be to see that Delhi emulates the worthy example of Hyderabad.

Then I want that the Inspection Organisation, which is in existence in our department, which inspects the working of our various wings, should be suitably strengthened to see that there is real and efficient working, because I do not want any delay in the service rendered by my department Shri Mahida said that two letters were delivered to him very late Whenever any letter, money order, parcel or anything of that nature is received by a postal unit, it must be promptly delivered to the person to whom it is addressed

In addition to that, we are going to set up an Efficiency Bureau in the department I have already asked the department to go into it and they are working on it We want that the work done by the department and its employees is properly analysed and everybody is induced to put in his best in the department

Then, we propose to fix a time limit as to how soon a telegram or a money order should reach the addressee. We want to ensure that a money order will reach the addressee within a week if he is in any corner of India. Similarly, a telegram must reach the person, even if he is in the mountains, within 12 hours from any place in India. I would see to it that this matter is gone into and the schedules which are fixed are strictly adhered to.

Regarding housing and other facilities, it is true that the postal personnel is very badly housed. Housing facilities are available only for 4.2 per cent of the personnel (shame, shame). Yes, it is a shameful matter but this has been the tradition.

Shri S. Kandu: In this department shame has become a tradition

Dr. Ram Subhag Singh: As Shri Gujral has pointed out, we have made a provision of Rs. 15 crores during this Plan. But we are not going to be satisfied only with this. The moment our ways and means position improves, we will make suitable additional allocations for this purpose

Regarding the welfare activities, there are about 9 dispensaries and we will go on improving these facilities. Then, I am happy to say that, just like railways, P. & T. department has already started giving scholarships to the sons and daughters of the P. & T employees For technical degree the number is 300, the amount per month is Rs 50 and it is tenable for four years, for technical diploma the number is 50, the amount per month is Rs. 30 and it is tenable for 3 years and the number of non-technical scholarships is 50 for Rs. 15 to Rs 20 per month tenable for three years We wdl also increase these.

There were two tests recently for the entire nation. These tests were the war with Pakistan and with China. The general election was also a test for our nation If anybody examines the performance of the P. & T. Department during those three critical periods, I think, he would not be ashamed of the performance of the P. & T Department. I take this opportunity to congratulate all the employees of the P & T who acquitted themselves well during the time of that ordeal and I hope during the coming years also they will prove their *bona fides*.

Shri Nambiar: About the extra-departmental employees the hon. Minister stated that he will have..... *(Interruption)*

Mr. Speaker: I will now put all the cut motions to the vote of the House .....*(Interruption)*

Some hon. Members rose—

Mr. Speaker: We are daily losing time on the Demands. On Food Demands we are losing time; on other Demands we are losing time. Three hours are allotted for a particular Demand and it goes on for five hours.

Shri Nambiar: He has promised.. ...

Mr. Speaker: Whatever promise he has made. I am not responsible for it. I am putting all the cut motions now to the vote of the House

Shri Nambiar: If he gives a promise that he will look to the extra-departmental employees, we will not press them.

All the motions were put and negatived

Mr. Speaker: Now I am putting the Demands to the vote of the House.

Shri Nambiar: Let him give a promise

Mr. Speaker: The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts shown in the fourth column of the order paper, be granted to the President, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1968, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 93 to 97, 142 and 143 relating to the Department of Communications."

The motion was adopted.

[*The motions for Demands for Grants which were adopted by the Lok Sabha, are reproduced below—Ed.*]

DEMAND No. 93—DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

"That a sum not exceeding Rs. 8,34,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1968, in respect of Department of Communications."

DEMAND No. 94—OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE

"That a sum not exceeding Rs. 1,55,68,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1968, in respect of Overseas Communications Service."

DEMAND No. 95—POSTS AND TELEGRAPHS (WORKING EXPENSES)

"That a sum not exceeding Rs. 1,17,09,67,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1968, in respect of Posts and Telegraphs (Working Expenses)."

DEMAND No. 96—POSTS AND TELEGRAPHS DIVIDEND TO GENERAL REVENUE AND APPROPRIATIONS TO RESERVE FUNDS

"That a sum not exceeding Rs. 13,61,86,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1968, in respect of Posts and Telegraphs Dividend to General Revenue and Appropriations to Reserve Funds."

DEMAND No. 97—OTHER REVENUE EXPENDATURE OF THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

"That a sum not exceeding Rs. 21,60,000 be granted to the

President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1968, in respect of Other Revenue Expenditure of the Department of Communications"

DEMAND NO 142—CAPITAL OUTLAY ON POSTS AND TELEGRAPHS (NOT MET FROM REVENUE)

"That a sum not exceeding Rs. 38,42.00,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1968, in respect of Capital Outlay on Posts and Telegraphs (Not met from Revenue)"

DEMAND No. 143—OTHER CAPITAL OUTLAY OF THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

"That a sum not exceeding Rs 1,15,57,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1968, in respect of Other Capital Outlay of the Department of Communications."

10.22 hrs.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVFLOPMENT AND COOPERATION.

Mr. Speaker: The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 32 to 37, 121 and 122 relating to the Ministry of Food, Agriculture, Community development and Cooperation for which 10 hours have been allotted.

Hon. Members present in the House who are desirous of moving their cut motions may send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move.

DEMAND NO. 32—MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION.

Mr. Speaker: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 99,29,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charge which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1968, in respect of Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation"

DEMAND NO. 33—AGRICULTURE

Mr. Speaker: Motion moved·

"That a sum not exceeding Rs. 6,17,89,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1968, in respect of Agriculure"

DEMAND NO 34—PAYMENTS TO INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

Mr. Speaker: Motion moved

"That a sum not exceeding Rs. 11,00,39,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charge which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1968, in respect of 'Payments to Indian Council of Agricultural Research."

DEMAND NO 35—COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECTS AND NATIONAL EXTENSION SERVICE

Mr. Speaker: Motion moved·

"That a sum not exceeding Rs. 7,60,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1968, in respect of 'Community development Projects and National Extension Service."